सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष

रामपुर तिराहा (मुजफ्फरनगर) शहीद स्थल

खटीमा स्थित शहीद स्थल

मसूरी स्थित शहीद स्थल

देहरादून स्थित शहीद स्थल

शत्-शत् नमन

संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार के सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई !

21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं – अपनी विरासत पर गर्व और विकास के लिए हर संभव प्रयास। उत्तराखण्ड इन दोनों स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। देवभूमि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को संजोते हुए आधुनिक बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के नए अवसरों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर राज्य की जनता को हार्दिक बधाई!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डबल इंजन सरकार की नीति के साथ उत्तराखण्ड निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बीते वर्षों में प्रदेश ने बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्वरोजगार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उत्तराखण्ड अपनी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक पहचान को संजोते हुए आधुनिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि सरकार की दूरदर्शी नीतियां राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और यह दशक उत्तराखण्ड के स्वर्णिम भविष्य का आधार बनेगा।

प्रदेश की जनता को सुख, समृद्धि और निरंतर विकास की शुभकामनाएं!

अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार

राज्य आंदोलन
के
शहीदों को
शत्-शत् नमन

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001
फोन : 0135-2650433 (का.)
0135-2716262
फैक्स : 0135-2712827
ई मेल : cm-ua@nic.in

संदेश

देवभूमि उत्तराखण्ड के मेरे सम्मानित भाइयो और बहिनों,

आप सभी के आशीर्वाद से वर्तमान सरकार ने तीन वर्ष का मंजिल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर मैं उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदेश में विभिन्न दुर्घटनाओं और आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, हमारी कोशिश है कि हर पीड़ित की हर संभव मदद हो और वे एक बार फिर से सामान्य जीवन शुरू कर सकें।

पिछले तीन वर्षों के सफल कार्यकाल में हमने समृद्ध, सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की ओर तेजी से कदम बढ़ाये हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड, प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। यह कालखण्ड उत्तराखण्ड के लिये आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थापना संरचना की दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहा है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ सशक्त उत्तराखण्ड की अवधारणा को साकार करने के लिये राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई नये आयाम स्थापित किये हैं।

वर्ष 2022 के विधान सभा चुनावों में राज्य की देवतुल्य जनता ने एक ही दल की सरकार को दुबारा सत्ता सौंपने के मिथक को तोड़ते हुए भारी जनादेश के साथ पूर्व की सरकार को दुबारा सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने का अवसर दिया। राज्य के विकास के प्रति हमारी स्पष्ट सोच का ही परिणाम है कि आज उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने में न केवल सफल रहा है, बल्कि राज्य हित में लिये गये कई नीतिगत निर्णयों का भी अन्य राज्य अनुसरण करने में आगे आ रहे हैं। हमने अपनी सकारात्मक एवं विकासोन्मुखी संकल्प दृष्टि के साथ राज्य के समग्र विकास का रोड मैप तैयार किया है। इसी का परिणाम है कि उत्तराखण्ड आज देश के अग्रणी राज्यों के समक्ष अपने स्पष्ट विजन के साथ खड़ा है।

2022 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश की जनता से किये गये वायदे के अनुसार हमने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता को मंजूरी देकर उत्तराखण्ड को देश का पहला राज्य बना दिया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लायी गयी है। समान नागरिक संहिता में सभी धर्म-समुदायों की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपति में समान अधिकार देते हुए सशक्त बनाया गया है। साथ ही सभी धर्म-समुदायों में सभी वर्गों के लिये बेटा-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार दिये जाने जैसे कई प्राविधान किये गये हैं।

राज्य आंदोलन के मूल में उत्तराखण्ड के समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा रही थी। इस भावना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा पारदर्शिता, जन सहभागिता और नई कार्य संस्कृति के साथ विकास की नई गाथा लिखने की उल्लेखनीय पहल की गई है। हमने समृद्ध, सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की ओर तेजी से कदम बढ़ाये हैं।

हमारी सरकार, प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने के लिये राज्य में सशक्त उत्तराखण्ड मिशन लांच किया गया है, जिसके अंतर्गत जीएसडीपी को दोगुना किये जाने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा राज्य, तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2023-24 के एस.डी.जी. इंडेक्स में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है।

राज्य की जी.एस.डी.पी. में 1.3 गुना वृद्धि हुई है, जबकि राज्य की, प्रति व्यक्ति आय में पिछले दो वर्षों में 26 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जीएसटी संग्रहण में इस वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल से सितंबर की बात करें तो इस अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खनन राजस्व में 78 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

हमारे राज्य को गत वर्ष जी-20 की तीन बैठकों के आयोजन का अवसर मिलना एक उपलब्धि है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड के लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि अपने साथ राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति के बेहतरीन अनुभव लेकर यहां से लौटे हैं।

हमारे लिए यह भी गौरव की बात है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन का अवसर हमारे राज्य को मिला। हमारी सरकार की खेल नीतियों का प्रभाव रहा कि राष्ट्रीय खेलों में राज्य के युवा खिलाड़ियों द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकार्ड बनाया। विगत राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड 25 वें स्थान पर था, जबकि इस बार पहले सात स्थानों में शामिल रहा।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में लगभग दो लाख करोड़ की योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण कार्य तेजी से हुआ है। बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य गतिमान हैं। इसी प्रकार मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में उत्तराखण्ड में कनेक्टिविटी में काफी काम हुआ है। ऑल वेदर रोड से चार धाम यात्रा को सुगम किया गया है। दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर केवल दो से ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही पहाड़ में रेल का सपना साकार होने जा रहा है। प्रदेश की आर्थिकी के विकास और आवागमन में ये योजना क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन पर भी सर्वे किया जा चुका है और जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखण्ड को केंद्र से दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिली है। जौलीग्रान्ट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए कार्य गतिमान है। राज्य में विभिन्न स्थानों के लिये हेली सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं। केन्द्र सरकार की 'रीजनल कनेक्टिविटी योजना' के अंतर्गत अनेक स्थानों पर हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है। पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे का शुभारम्भ किया जा चुका है।

राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये हमारी सरकार ने निवेश अनुकूल वातावरण बनाया है। राज्य में बेहतर औद्योगिक सद्भाव, बिजली की अपेक्षाकृत कम दरों पर उपलब्धता, बेहतर कानून व्यवस्था, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम के कारण उत्तराखण्ड इन वर्षों में निवेशकों की पसंद के तौर पर उभरा है। पिछले वर्ष हमने इन्वेस्टर्स समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस अवसर पर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिला। हमने उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों से सुझाव लेकर 30 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के उद्यमियों द्वारा 3 लाख 56 हजार करोड़ के एमओयू किये गए। इनमें से 85 हजार करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग की कार्यवाही गतिमान है।

ऊधमसिंहनगर के खुरपिया फार्म किच्छा में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीयल कोरिडोर परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने स्मार्ट इंडस्ट्रीयल टाउनशिप बनाए जाने की स्वीकृति दी है। इस परियोजना से राज्य में विनिर्माण उद्योगों में पूंजी निवेश के साथ राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर और अधिक रोजगार उपलब्ध होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिये पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आइटी और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। सीमांत क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है।

वाइब्रेंट विलेज योजना से उत्तराखण्ड के सीमावर्ती गांवों का विकास हो रहा है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित 'एक जनपद दो उत्पाद योजना' से स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं। राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड प्रारम्भ किया गया है। उत्तराखण्ड के मिलेट को सुपर फूड के रूप में देश भर में पहचान मिली है। प्रदेश में चार हजार से अधिक क्लस्टरों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के लगभग 9 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक योजना में 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। बहुप्रतीक्षित बहुद्देशीय जमरानी, सौंग और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है।

प्रदेश में पलायन रोकने के लिये विभिन्न रोजगार एवं स्वरोजगार परक योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जा रहा है। गाँवों को गोद लेकर उनका विकास करने की योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। राज्य में आयोजित अर्न्तराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन तथा प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन के माध्यम से पलायन से खाली हुए गाँवों को गोद लेकर विकसित करने का भी संकल्प लिया गया है। प्रवासियों द्वारा गाँव को गोद लेने की अवधारणा हमारे गाँव के लिये नई प्रेरणा है।

उत्तराखंड की पारंपरिक कला और संस्कृति की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देने लगी है. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्तराखंड की लोक कलाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे राज्य को वैश्विक पहचान और सम्मान मिल रहा है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति अपने आप में अद्वितीय और गौरवशाली है। हमारी संस्कृति ही हमारी मूल पहचान है, चाहे हम जीवन में किसी भी स्तर पर पहुँचें या दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमारी पहली पहचान ये है कि हम उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं और विरासत हमारी आत्मा का हिस्सा हैं।

हमारे युवा सकारात्मक सोच के साथ राज्य की लोक परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ सकें, इसके लिये राज्य में साहित्य एवं ललित कला केंद्रों की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राज्य के युवाओं को फिल्मों के साथ ही साहित्य एवं लोक संस्कृति, लोक कला की विभिन्न विधाओं से जुड़ने का अवसर मिल सके।

देवभूमि उत्तराखण्ड सदियों से रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र रही है। यहां के पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। किसी भी समाज का साहित्य ही उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करता है। राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति को बेहतर वित्तीय प्रबंधन व स्थान विशेष की विशिष्टता की पहचान के साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य की विकट भौगोलिक परिस्थिति अब वरदान साबित होने जा रही है। जल, जंगल व ज़मीन राज्य के सतत विकास के आधार बनें, इसके लिये प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड में विगत वर्षों में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने लिए हैं, जो विगत 24 वर्षों में संभव नहीं हो पाये थे। हमने एक ओर जहां उत्तराखण्ड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया, प्रदेश में पहली बार कार्रवाई कर पांच हजार हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। उत्तराखण्ड देवभूमि है, हमारी देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

हमारी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारा उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा की नीति लाई गई है। प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिये 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों के डिस्पोजल में उत्तराखण्ड देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ी है। आज प्रदेश में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है।

हमारी सरकार युवाओं की सरकार है। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर नकल माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। भर्ती घोटालों में शामिल 100 से अधिक अपराधियों को जेल भेजा गया है। नकल माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिये राज्य में की गई पहल पूरे देश में नजीर बनी है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से भर्तियां हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी सेवाओं में लगभग 20 हजार से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं। आगे भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। टोल-फ्री नम्बर 1064 भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। अपणि सरकार पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था से सुशासन की परिकल्पना साकार हो रही है। जनता से जुड़ी योजनाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उत्तराखंड असीम संभावनाओं का प्रदेश है। प्रकृति द्वारा इसे संसाधनों से परिपूर्ण बनाया गया है। जलविद्युत परियोजनाओं के साथ पर्यटन राज्य की आर्थिकी का मज़बूत आधार है।

उत्तराखण्ड को बहुआयामी पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर काम किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक और सामान्य पर्यटन के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए क्षेत्रों को पर्यटन के अंतर्गत लाया जा रहा है। उत्तराखण्ड विश्व के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। सुगम सुरक्षित चारधाम यात्रा हमारी प्राथमिकता रही है। बेहतर कनेक्टिविटी और चारधाम में की गई बेहतर व्यवस्थाओं से इस वर्ष लगभग 45 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन हेतु आये। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बाबा केदार के दर्शनों को अनेक बार आ चुके हैं। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम आने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।

हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब भारत भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। हाल ही में उत्तराखण्ड के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांवों को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इस वर्ष से राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन यात्रा की अनूठी पहल शुरू की है, इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय रोजगार के साथ आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। राज्य में इको-टूरीज्म को बढ़ावा देने के लिये भी नीति तैयार की गई है। इसके तहत इको-टूरीज्म गंतव्य विकसित कर आजीविका के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मुखवा और हर्षिल यात्रा प्रदेश के शीतकालीन यात्रा को नई ऊँचाई तक ले जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वेड इन उत्तराखण्ड की अपील के बाद, उत्तराखण्ड की वैडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन रही है। हमारी सरकार पर्यटन से स्थानीय आजीविका को मजबूती देने का प्रयास कर रही है। आज राज्य के होम स्टे देश-विदेश के पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। होम-स्टे योजना राज्य के युवाओं और मातृशक्ति के लिए स्वरोजगार का माध्यम बन रही है।

राज्य सरकार फिल्म निर्माण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फिल्म निर्माण से राज्य में प्रत्यक्ष रोज़गार की नयी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही राज्य के पर्यटन को नयी मज़बूती मिलेगी। नए शूटिंग डेस्टिनशनों को भी पर्यटन विभाग के सहयोग से चिन्हित कर उनको भी शूटिंग के लिए प्रचारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे फिल्मों के माध्यम से उत्तराखंड के अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भी प्रचार हो सकेगा।

हमारी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड की पहचान फिल्म शूटिंग के डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। नई फिल्म नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। आज प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए बाहर से अनेक फिल्म निर्माता आ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारी स्थानीय भाषा में भी फिल्में बन रही हैं। मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया है।

स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करने में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में है। राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना की गई है। 840 नए विद्यालयों में स्मार्ट क्लास गतिमान हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राज्य के राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी सत्र से कॉपियां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव की क्षमता रखने वाले विद्या समीक्षा केन्द्र का शुभारम्भ हो चुका है। अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना शुरू की गई है।

हमारी सरकार द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। ऊधमसिंहनगर के किच्छा में एम्स का सैटेलाईट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पिछले तीन वर्षों में राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेज शुरू किये गये हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एम्स ऋषिकेश से देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का शुभारंभ किया है। जल्द ही इसका टोल फ्री नंबर जारी होगा जिसे सभी 13 जिलों के जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन की सिफारिश पर तत्काल हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्तराखण्ड योग और आयुष की भूमि है आयुष का परम्परागत ज्ञान देश-विदेश तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। इसी उद्देश्य से हाल ही में विश्व आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस एवं आरोग्य एक्सपो-24 का अभूतपूर्व आयोजन किया गया, इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने तथा शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मातृशक्ति का सम्मान हमारी परम्परा रही है। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही सहकारी समितियों में भी राज्य की महिलाओं के 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। 2026 तक ढाई लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उत्तराखण्ड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की व्यवस्था की जा रही है।

हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन में वृद्धि के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों और पात्र आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि में भी वृद्धि की है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के साथ ही प्रदेश के लोक कलाकारों का मानदेय भी दोगुना किया गया है। अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत वर्ष में 3 गैस सिलैण्डर रिफिल मुफ्त दिये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। हमें अपनी सैनिक परम्परा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण भी किया गया है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य का सरकारी नौकरी में समायोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को कई गुना बढ़ाते हुए 50 लाख रूपए किया गया है। हम अपने सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आज उत्तराखण्ड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में जन-आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार समावेशी विकास के मूलमंत्र पर विश्वास करते हुए सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं समान विकास के लिए कार्य कर रही है। जन सेवा, सुशासन, संवेदनशीलता और गरीब कल्याण हमारा ध्येय है। ब्लॉक स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर जन समस्याओं की सुनवाई हो रही है। जन समस्याओं के त्वरित निवारण पर बल दिया जा रहा है।

प्रदेशवासियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि को केंद्र बिंदु मानकर कार्य किया जा रहा है। हमने इस मंत्र की सहायता से प्रदेश में कार्य संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को ध्येय वाक्य मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास में देवभूमि की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, इसके लिये हम निरन्तर प्रयासरत हैं। रजत जयंती वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो, यही हमारा संकल्प है।

जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड !

(पुष्कर सिंह धामी)
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

ऐतिहासिक पहल

शीतकालीन यात्रा पर मुखवा–हर्षिल आये प्रधानमंत्री ने उत्तराखण्ड के पर्यटन को दिये नये आयाम

प्रधानमंत्री मोदी जी फिर साबित हुए सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखण्ड में कोई 'ऑफ-सीजन' नहीं होना चाहिए और पर्यटन को हर मौसम में फलना-फूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पहाड़ों का पर्यटन मौसमी है, जिसमें मार्च, अप्रैल, मई और जून के दौरान पर्यटकों की अच्छी-खासी आमद होती है। हालांकि, इसके बाद पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आती है, जिससे सर्दियों के दौरान अधिकांश होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे खाली हो जाते हैं। इस असंतुलन के कारण उत्तराखण्ड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक ठहराव बना रहता है और पर्यावरण के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा सर्दियों के दौरान उत्तराखण्ड की यात्रा करने से देवभूमि की दिव्य आभा की सच्ची झलक मिलती है। विंटर टूरिज्म में यहां, लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। उत्तराखण्ड में धार्मिक यात्राओं के लिए सर्दियां विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि इस दौरान कई पवित्र स्थलों पर अनोखे अनुष्ठान किए जाते हैं। उन्होंने मुखवा गांव में होने वाले धार्मिक समारोहों को क्षेत्र की प्राचीन और महत्वपूर्ण परंपराओं का अभिन्न अंग बताया।

`घाम तापो' के तौर पर की उत्तराखण्ड विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग

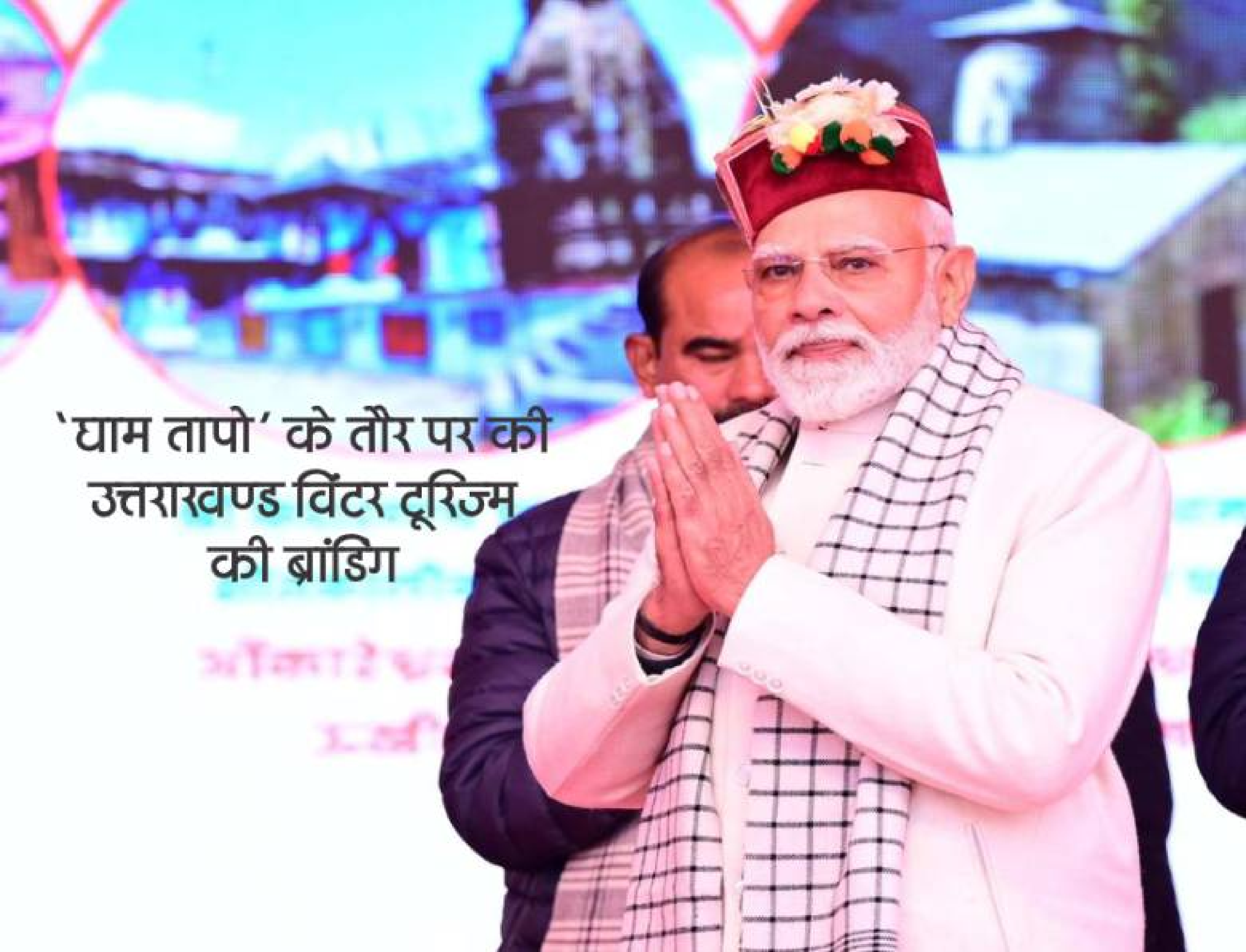

रजत जयंती वर्ष
विंटर टूरिज्म के लिए अभिनव प्रयास

प्रधानमंत्री का मिला साथ, दौड़ेगी यात्रा, बनेगी बात।

शीतकालीन यात्रा को तो पहल से ही, चार धाम यात्रा के लिए भी आधार किया तैयार।

कम समय में देश-दुनिया की नजरों में आई शीतकालन यात्रा।

प्रमोशन के लिए 'घाम तापो' पर्यटन की बात हो, धर्माचार्यों और योगाचार्यों द्वारा शीतकाल में योग शिविर आयोजित करने की बात हो, कॉरपोरेट को सेमिनार का सुझाव हो, फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग एवं वैडिंग डेस्टिनेशन के लिए आह्वान हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हो अपील। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री की पहल का हुआ असर

प्रधानमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 मोटर बाइक रैली एवं 2 ट्रैक रूट दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

प्रधानमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन के साथ शीतकालीन साहसिक खेलों को दिखाई राह।

प्रधानमंत्री के प्रयास से उत्तराखण्ड में बाइक रैली और ट्रैकिंग को मिलेगा बढ़ावा।

लद्दाख की तर्ज पर उत्तराखण्ड का हर्षिल क्षेत्र बनेगा देश का बड़ा मोटर बाईक डेस्टिनेशन।

धार्मिक पर्यटन के साथ शीतकाल के समय उत्तराखण्ड में होने वाले साहसिक खेलों को भी मिलेगा बढ़ावा।

शीतकालीन यात्रा : आर्थिकी को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड को समृद्ध बनाने का मार्ग है
चार धाम यात्रा

चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाए जाने हेतु सभी
तीर्थ पुरोहितों के लिए सुझाव।

राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चार
धाम की यात्रा को और अधिक सफल बनाएगी

चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाए जाने हेतु सभी तीर्थ
पुरोहितों के सुझाव भी लिए।

"राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चार धामों की यात्रा को और अधिक सफल और बेहतर बनाने पर कार्य कर रही है। चार धामों के कपाट खुलने से पहले ही राज्य सरकार सभी तैयारियां पूर्ण करेगी। राज्य सरकार चार धामों के साथ ही शीतकालीन चार धाम यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री"

बाबा केदार के प्रांगण का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा चार धामों को बढ़ावा दिया है। आगे भी प्रधानमंत्री जी ने शीत कालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है।

शीतकालीन यात्रा को लेकर राज्य सरकार व्यापक प्रचार-प्रसार कर रही है। बीते वर्ष की यात्रा में जो कमियां रही थी, उन्हें इस वर्ष सुधारा जा रहा है। चार धाम के साथ हमें अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार कर उन्हें विकसित करना है, ताकि यहां भी अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुंचें। चार धाम यात्रा उत्तराखण्ड को समृद्ध बनाने का भी मार्ग है।

मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा के तहत उनके शीतकालीन स्थलों के पौराणिक महत्व एवं प्रभावी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थलों का प्राचीन काल से ही अपना विशिष्ट महत्व रहा है और श्रद्धालु इन स्थलों पर देव दर्शन करते रहे हैं। इन शीतकाल स्थलों के दर्शन से भी वही पुण्य प्राप्त होता है, जो नियमित यात्रा के दौरान होता है। शीतकाल में श्री केदारनाथ की ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, बदरीनाथ की पाण्डुकेश्वर और नृसिंह मंदिर ज्योर्तिमठ में, यमुनोत्री के खरसाली और गंगोत्री के मुखवा में पूजा-अर्चना होती है।

मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा के तहत उनके शीतकालीन स्थलों के पौराणिक महत्व एवं प्रभावी प्रचार-प्रसार करने के दिये निर्देश।

शीतकालीन पर्यटन को लगेंगे पंख

हर्षिल-मुखवा के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र में शीतकालीन यात्रा को पंख लगेंगे।

पूरे विश्व में उत्तराखण्ड में शीतकालीन पर्यटन यात्रा का प्रचार-प्रसार होगा। जिससे राज्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटकों का आगमन होना तय है। यह अवसर हमारे राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान साबित होने वाला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शीतकालीन यात्रा पर सरकार के प्रयासों को सराहा'।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था चारधाम यात्रा पर ही निर्भर नहीं रह सकती है। इसी दिशा में उत्तराखण्ड में अब शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा के साथ ही शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में होगी सहायक।

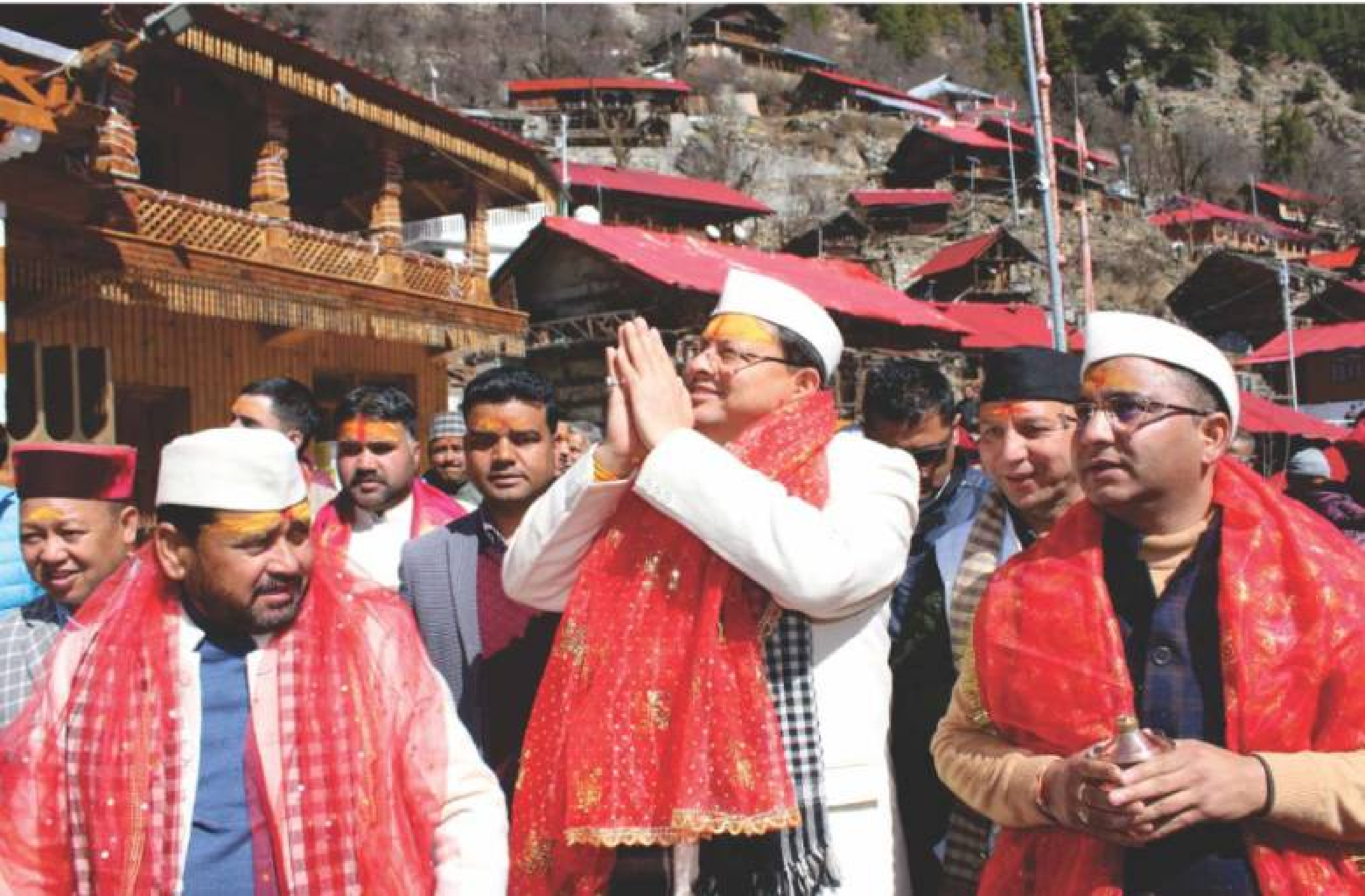

प्रधानमंत्री ने किया 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ

देहरादून, उत्तराखण्ड में

देवभूमि उत्तराखण्ड आज युवा ऊर्जा से और भी दिव्य हो उठा है, बाबा केदार, बद्रीनाथ जी, मां गंगा के शुभाशीष के साथ आज यहां नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखण्ड के निर्माण का 25वां वर्ष भी है, इस खास अवसर पर इस युवा राज्य में देश के अलग- अलग हिस्सों से आए, हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। इससे यहां एक भारत, श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर नजर आ रही है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

खेल से बढ़ती है देश की प्रोफाइल

“जहां भी ओलंपिक होते हैं वहां अनेक सेक्टर को गति मिलती है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं। ठीक ऐसे ही नेशनल गेम्स से यहां देवभूमि उत्तराखंड को अनेक लाभ मिलेंगे।”

दर्शकों की मोबाइल फ्लैश लाइट करवाई ऑन

“प्रधानमंत्री ने नेशनल गेम्स की विधिवत शुरुआत करते हुए कहा कि वैसे तो ये उनका दायित्व है, लेकिन वो चाहते हैं कि स्टेडियम में मौजूद सभी लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर, उनका साथ दें, जिस पर उपस्थित जन समुदाय ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का साथ दिया।”

उत्तराखण्ड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। विगत राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड 25वें स्थान पर था, इस बार उत्तराखण्ड पदक तालिका में सातवें स्थान में रहा।

शानदार मार्च पास्ट से खिलाड़ियों ने दी सलामी

“ओलंपियन शटलर लक्ष्य सेन ने मंच पर पहुंच कर तेजस्वनी मशाल प्रधानमंत्री को सौंपी। लक्ष्य सेन ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों की शपथ भी दिलाई। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के क्रम में 2025 शंख बजाकर, जोरदार शंखनाद किया गया।”

देवभूमि बनी खेलभूमि

28 जनवरी से 14 फरवरी 2025

यह वर्ष उत्तराखण्ड के निर्माण का 25वां वर्ष भी है, इस खास अवसर पर इस युवा राज्य में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। इससे यहां एक भारत, श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर नजर आ रही है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

पदक विजेताओं के नाम लगाये जायेंगे पौधे।

देशभर के लगभग 10,000 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग।

35 खेलों में प्रतियोगिताएं।

युवाओं को प्रेरित करने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ाया।

उत्तराखण्ड के लिए खेलों की मेजबानी का ऐतिहासिक अवसर।

उत्तराखण्ड के खेल परिदृश्य के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर।

देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन।

आकर्षण

- मौली (मैस्कट): युवा एथलीटों को ऊंचे लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाला उत्तराखण्ड का राज्य पक्षी मोनाल।
- तेजस्विनी (मशाल): परंपरा, एकता और खेल भावना का प्रतीक।

३८वें राष्ट्रीय खेलों का हुआ भव्य समापन

“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आया है। देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग की व्यवस्था, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन के माध्यम से आज विश्व के खेल पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।”

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

३८वें राष्ट्रीय खेल: ग्रीन गेम्स की थीम पर किया गया आयोजित

राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड में नई संभावनाओं और उम्मीदों की शुरुआत।

उत्तराखण्ड की देवभूमि के साथ खेलभूमि के तौर पर भी बनी पहचान। उत्तराखण्ड के हर जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार।

देवभूमि को राष्ट्रीय खेलों के नक्शे पर 25वें स्थान से 7वें स्थान पर लाने का कार्य किया है। खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 103 पदक अर्जित किए।

इको- फ्रेंडली प्रैक्टिसेज एवं इको-फ्रेंडली गेम को धरातल में उतारा गया है। खिलाड़ियों के नाम पर पौधारोपण किया गया।

आगामी ओलंपिक में उत्तराखण्ड के खिलाड़ी भी मेडल लाकर भारत के तिरंगे का मान बढ़ाएंगे।

शिखर पर खेल भूमि

राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्म नौकरी का प्रावधान।

खेल कोच का मानदेय बढ़ाकर किया गया दोगुना।

सरकारी सेवा में पदक विजेताओं को 4% आरक्षण का प्रावधान।

राष्ट्रीय खेलों में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की गई दोगुना।

स्वर्ण पदक विजेता की प्रोत्साहन धनराशि 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख।

रजत विजेताओं की प्रोत्साहन धनराशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख।

कांस्य पदक विजेताओं की प्रोत्साहन धनराशि 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई।

सरकार के ऐतिहासिक फैसले

न भूतो न भविष्यति।।

समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना।

देश का सख्त - नकल विरोधी कानून लागू करने वाला बना पहला राज्य।

सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला बना राज्य।

राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान।

20 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से दी गई नियुक्ति।

जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू-कानून को लागू किया गया।

जबरन धर्मान्तरण की रोकथाम को लेकर बना कठोर कानून।

समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू समाप्त।

नए युग का शुभारम्भ : समान नागरिक संहिता

समरसता से समानता

जो कहा था उसे करके दिखाया

सिद्ध होते संकल्प

स्वतंत्र भारत के इतिहास में

उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला राज्य बना

यूसीसी की यात्रा

27 मई 2022	यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन
02 फरवरी 2024	यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
08 फरवरी 2024	राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित
08 मार्च 2024	भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित
12 मार्च 2024	यूसीसी उत्तराखण्ड अधिनियम 2024 जारी
18 अक्टूबर 2024	यूसीसी नियमावली प्रस्तुत
27 जनवरी 2025	यूसीसी लागू

यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्य योजना

- उत्तराखण्ड राज्य में न्यूनतम एक वर्ष से निवास करने वाले भी यूसीसी के दायरे में होंगे। यूसीसी पंजीकरण का उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। पंजीकरण का उद्देश्य उत्तराखण्ड डेमोग्राफी को संरक्षित करना है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc-uk-gov-in) विकसित।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामित।
- क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए जिलों में नोडल अधिकारी नामित।
- सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापित।
- विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त।
- नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए Short Video एवं Booklets ।

प्रयागराज महाकुंभ में
समान नागरिक संहिता की गूंज

2027 कुंभ मेला हरिद्वार

कुंभ मेले के भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी से प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रयाग राज महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को इसके लिए अभी से व्यवस्थाओं हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए बजट में वित्तीय व्यवस्था भी की गई है।

"प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना में पूज्य संतों का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। समान नागरिक संहिता लागू करना, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। मेरा जो सम्मान संतों ने किया है, वो उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प रखा था। जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। सरकार बनने के बाद सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया गया।"

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

समान नागरिक संहिता लागू करने पर संत समाज ने प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री का किया अभिनंदन।

"भारत के सभी संत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं। छोटा राज्य होने के बाद भी उत्तराखंड सबसे बड़ा बन गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता सबसे पहले लागू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करके भारत को बल दिया है। अब उत्तराखंड के साथ अन्य राज्य भी यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ाएंगे।"

महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज

जनभावनाओं के अनुरूप बनाया भू-कानून

हमारा संकल्प उत्तराखण्ड के संसाधनों, जमीनों को बचाए रखना है। यह संशोधन भू-सुधारों की दिशा में एक शुरुआत है। राज्य सरकार ने जन-भावनाओं के अनुरूप भू-सुधारों की नींव रखी है। भू-प्रबंधन एवं भू-सुधार पर आगे भी अनवरत रूप से कार्य किया जाएगा।

राज्य सरकार ने राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया है। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण मामलों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। जिन उद्देश्यों से लोगों ने जमीन खरीदी है, उसका सही उपयोग हो, ये चिंता हमेशा मन में थी। उत्तराखण्ड में पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाके भी हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थिति एवं चुनौतियां अलग-अलग हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल जी ने उत्तराखण्ड राज्य के लिए औद्योगिक पैकेज दिया तब से राज्य सरकार बड़ी संख्या में औद्योगीकरण को बढ़ावा दे रही है। राज्य में आने वाले निवेशकों को अनुकूल वातावरण मिले, इसके लिए नीतियों में हमने सभी विषयों को समाहित किया है। राज्य सरकार सबकी भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून के लिए समिति बनाई गई एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू-कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई।

राज्य सरकार भू-कानून को लेकर गंभीर है। प्रदेश में लागू होने वाले भू-कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें भू-कानून में शामिल किया गया है। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू-कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए गये, जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया गया।

राज्य में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भू-कानून लागू किया जा रहा है। जनभावनाएं जिस तरह के सख्त भू-कानून के पक्ष में थीं, उसी अनुरूप इसमें प्राविधान किए गए हैं। इससे उत्तराखण्ड के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो पाएगी।

उत्तराखण्ड
भू-कानून
पर चर्चा
में आपका

उत्तराखण्ड को मिला सख्त भू-कानून 2025

- कृषि व बागवानी के लिए साढ़े बारह एकड़ भूमि खरीदने की छूट से जमीनों के खुर्द-बुर्द होने की शिकायतों पर सरकार ने करारी चोट की है। राज्य की धामी सरकार ने हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य सभी 11 जिलों में इस छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यानी पर्वतीय जिलों में अब कृषि व बागवानी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन ही नहीं खरीद पाएगा। जिन दो जिलों हरिद्वार व उधमसिंहनगर में इस छूट को खत्म नहीं किया गया है, वहां पर भूमि खरीद की प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया है। कृषि व बागवानी के लिए भूमि खरीद की अनुमति पहले डीएम स्तर से दे दी जाती थी। मगर अब इन दो जिलों में इसके लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, यह प्रावधान भी किया गया है कि कृषि व बागवानी के लिए भूमि खरीद का जो बाहरी व्यक्ति इच्छुक है, उसे संबंधित विभाग से आवश्यकता प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराना होगा।

- भू-कानून नगर निकाय और छावनी परिषद क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। बाहरी व्यक्ति यदि निकाय क्षेत्रों से बाहर आवास के लिए जमीन खरीदने का इच्छुक हो, तो उसके लिए भी प्रभावी व्यवस्था भू-कानून में कर दी गई है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक बार ही जमीन खरीद पाएगा और उसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर तक ही होगा। इसके लिए उसे अनिवार्य रूप से शपथपत्र भी देना होगा।

- भू-कानून में प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि का उपयोग निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही किया जाएगा। अन्यथा, कि स्थिति में संबंधित भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जाएगी। भूमि खरीद के लिए शपथपत्र की अनिवार्यता के पीछे यही मंशा है कि दुरूपयोग न होने पाए। इसी तरह, पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों के लिए यह जरूरी किया गया है कि वह राजस्व परिषद और शासन को भूमि खरीद प्रक्रिया की नियमित रिपोर्टिंग करेंगे।

3 साल बेमिसाल

सबका साथ
सबका विकास
सबका विश्वास
सबका प्रयास

सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और
सन्तुष्टि की नीति पर चल रही है सरकार।

उत्तराखण्ड के अंतिम छोर पर खड़े
व्यक्ति तक पहुंच रहा है विकास का लाभ।

उत्तराखण्ड को मिला देश का सख्त नकल विरोधी कानून

(भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय 2023)

संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ यदि कोई षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान।

दोबारा नकल करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो क्रमशः पांच से दस वर्ष के लिए अथवा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान।

दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाये जाने पर न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम ₹ 10 लाख जुर्माने का प्रावधान ।

अनुचित साधनों के प्रयोग में यदि कोई लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम ₹ 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोष सिद्ध ठहराये जाने की दशा में दस वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान।

अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय होगा।

अर्जित सम्पति की कुर्की करने का प्रावधान।

जबरन धर्मान्तरण को माना जायेगा संज्ञेय अपराध

सामूहिक धर्मान्तरण का दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान।

₹ 50 हजार तक का जुर्माना।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की भी देनी होगी सूचना।

घटित हो रही धर्मान्तरण की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सख्त धर्मान्तरण कानून लागू।

देवभूमि में धर्मान्तरण पर रोक के लिए प्रभावी व्यवस्था किया जाना समय की मांग थी।

उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश)

कानून को मंजूरी

"राज्य के लिए उत्तराखण्ड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून अति आवश्यक है। कानून बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि कोई भी इस प्रकार का अपराध करने की सोचे भी नहीं। देवभूमि में कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो संपत्ति के नुकसान की एक-एक पाई उसी दंगाई से वसूली जाएगी।"

गैरसैंण विस सत्र में पारित हुआ था विधेयक, अब दंगाईयों से ही होगी क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई।

एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी इस दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा।

इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलन में सरकारी के साथ-साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी।

दावे का निपटारा भी निश्चित समय अवधि में होगा, ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई हो सके।

इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसी का निर्माण

'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तराखण्ड'
देहरादून में प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

बनाई गई 27 नीतियों में ऑटोमोबाइल, औषधि, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा, फिल्म शूटिंग, अक्षय ऊर्जा, आयुष एवं वैलनेस, जैव प्रौद्योगिकी, हॉर्टिकल्चर एवं फ्लोरीकल्चर, हर्बल एवं एरोमैटिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, नेचुरल फाइबर विषयों को किया गया है शामिल।

उत्तराखण्ड सरकार की प्रमुख नीतियां

सेवा क्षेत्र नीति 2023, सौर ऊर्जा नीति 2023

एमएसएमई नीति 2023, स्टार्ट-अप नीति 2023, कस्टमाइज्ड पैकेज, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023, फिल्म नीति 2015 (2019 में संशोधित), निजी औद्योगिक पार्क नीति 2023, वृहद् औद्योगिक नीति 2015, निर्यात नीति 2021, पर्यटन नीति 2023-30, ड्रोन नीति 2023, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2019, आयुष एवं वैलनेस नीति, आबकारी नीति 2021-23, जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018-23, खाद्य प्रसंस्करण नीति, पंप भंडारण परियोजना नीति 2023।

प्रदेश की समृद्धि में भागीदार बनें

- पारदर्शी कर नीतियां और परियोजनाओं के लिए त्वरित स्वीकृति।
- आईआईटी सहित बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थान।
- शुद्ध पर्यावरण से स्वस्थ एवं बेहतर जीवन।
- राज्य सरकार की आकर्षक निवेश नीति
- एनसीआर या अन्य शहरों की तुलना में कम लागत पर उद्योग स्थापना।
- सुशासन और शांतिपूर्ण राज्य के रूप में पहचान।
- एनसीआर के साथ रेल, सड़क और हवाई मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से
रोजगार को
मिला बढ़ावा

जी20 की बैठकों से उत्तराखण्ड को मिली

ग्लोबल पहचान

- रामनगर 28–30 मार्च 2023
  मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन सम्पन्न।
- नरेंद्र नगर 25–27 मई 2023
  एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप सम्मेलन सम्पन्न।
- नरेंद्र नगर 26–28 जून 2023
  इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप सम्मेलन में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले।

खुलेगा विकास का द्वार

उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति 2023

लॉजिस्टिक्स पार्क की होगी स्थापना।

एयर कार्गो कॉम्पलेक्स से एयर कार्गो मूवमेन्ट की बढ़ेगी क्षमता।

वेयर हाउस बनाने की राह हुई आसान, भंडारण की सुविधा होगी अधिक प्रभावी।

कोल्ड चेन सुविधा से कृषि, बागवानी, डेयरी व अन्य खाद्य सामग्री की होगी सुरक्षा

राष्ट्रीय एवं वैश्विक एजेंसियों के साथ होगा समन्वय।

लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य - सरलीकृत, सक्रिय एवं उत्तरदायी संस्थातंत्र का निर्माण।

अंतर्देशी कन्टेनर डिपो, कॉल्ड स्टोरेज, औद्योगिक सम्पदा, क्लस्टरों से रेल एवं सड़क की कनेक्टिविटी जैसे लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती।

- उत्तराखण्ड आने वाले कल में पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षिक करने की क्षमता से लैस होगा।
- विभिन्न हितधारकों के लक्ष्यों और हितों को साधते हुए यह नीति एक एकीकृत ढांचा प्रदान करती है, जिससे पर्यटन विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।
- पर्यटन नीति का उद्देश्य इसे एक टूरिज्म क्लस्टर और सर्किट के तौर पर विकसित करना है। ये पहल नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देगी।
- यह नीति उत्तराखण्ड की पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी महत्व प्रदान करती है।
- डिजिटल युग में उत्तराखण्ड का लक्ष्य पर्यटकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने की है। इसके तहत प्रचार, मार्केटिंग, बुकिंग, आरक्षण और सूचना प्रसार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शामिल है।
- निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करते हुए यह नीति आतिथ्य और पर्यटन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देती है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच यह सहयोगी दृष्टिकोण पर्यटन उद्योग में त्वरित विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा।
- पार्किंग सुविधाओं, शौचालयों, साइनेज, एटीएम और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।
- पर्यटन नीति-2030 ने इस दशक के अंत तक अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने की समय सीमा तय की है।
- 'स्थायी पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र' स्थापित करना है।

उत्तराखण्ड बना वेडिंग के लिए नया डेस्टिनेशन

उत्तराखण्ड पर्यटन नीति

सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल

उत्तराखण्ड पर्यटन में निवेश पर अब डेढ़ करोड़ तक सब्सिडी

- उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- 6 लाख तक की छूट सालाना ब्याज पर मिलेगी, स्टांप ड्यूटी माफ होगी।
- योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमी को प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70% रोजगार उपलब्ध करना आवश्यक होगा
- ₹ 5 करोड़ से कम की परियोजनाओं पर ₹ 1.5 करोड़ की सब्सिडी होगी।
- सीमान्त जिलों में 33 लाख के साथ ही 30% अतिरिक्त सब्सिडी होगी।

नये डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में पहचान बना रहा उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में नई रोपवे परियोजनाओं, रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। यह पहल पर्यावरण अनुकूल यात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे। अपने समृद्ध आध्यात्मिक, रोमांचकारी और सांस्कृतिक अनुभवों के साथ, उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करना जारी रखेगा।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड अपनी सुंदरता के अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी दुनिया भर में पहचान बनाने लगा है। यही कारण है कि यहां देश और दुनियां भर से लोग वेडिंग के लिए आ रहे हैं और सुनहरी यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे उत्तराखण्ड सतत् विकास के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। अपने प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी क्षमता को प्रदर्शित भी किया है। मैं समावेशी विकास के लिए राज्य के समर्पण की सराहना करता हूं और आने वाले वर्षों में इसकी निरंतर सफलता की आशा करता हूं।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023–2030

आधुनिक पर्यटन के साथ आध्यात्मिक अनुभूति

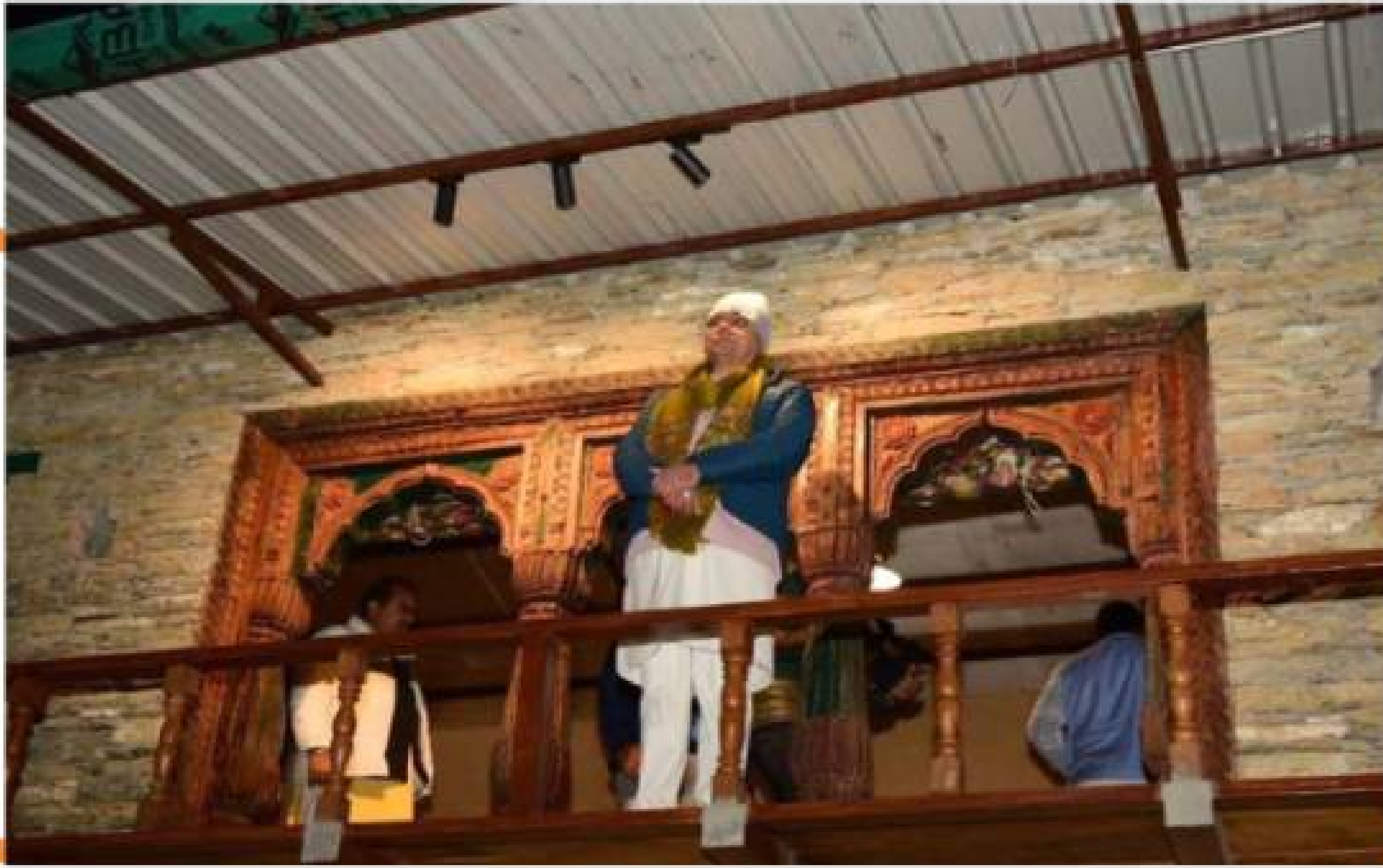

होमस्टे: राज्य में घर जैसा आतिथ्य

होमस्टे के मालिकों को सशक्त बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना

हिमालय की वादियों में खूबसूरत और मनमोहक स्थल मौजूद हैं।
होमस्टे पोर्टल राज्य के सभी होमस्टे के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार है।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राज्य में बड़े होटल स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए उत्तराखण्ड में होमस्टे मालिकों को बेहतर होमस्टे विकसित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन के प्रयास शुरू किए हैं।

यह रणनीति राज्य से पलायन को रोकने के लिए तैयार की गई है, जिससे ज्यादातर स्थानीय लोग होमस्टे स्थापित कर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही यह उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रहा है।

राज्य ने होमस्टे से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी सहायता प्रदान करना, कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना और एक समर्पित होमस्टे बुकिंग पोर्टल www.uttarastays.com शामिल है। इससे होमस्टे मालिकों को बिना किसी शुल्क के अपने होमस्टे को सूचीबद्ध करने की सुविधा मिलती है।

पर्यटन नई ऊँचाई पर

पूरे वर्ष चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों सहित पूरे प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू की गई।

- टिहरी एक्रो फेस्टिवल में विभिन्न देशों के विदेशी तथा देशी पैराग्लाइडिंग पायलटों द्वारा किया गया प्रतिभाग
- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के ग्राम जखोल को Best Tourism Village का पुरस्कार, बागेश्वर के ग्राम सूपी को Best Adventure Village पुरस्कार, पिथौरागढ़ के ग्राम गुंजी एवं उत्तरकाशी के ग्राम हर्षिल को Best Vibrant Village पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय खाली करवाये गये जांदुग गांव में जीर्ण-क्षीर्ण भवनों को पुनर्निर्मित करते हुए होम-स्टे के रूप में विकसित करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है।
- पर्यटन के क्षेत्र में 1 से ₹ 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों/उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आर्थिक रूप में सबल बनाये जाने के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 प्रारम्भ की गयी है।

आगामी चारधाम यात्रा होगी
ग्रीन चारधाम यात्रा

पुरखों की याद में पौधे रोपेंगे तीर्थ यात्री।

सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पर होगा प्रतिबंध।

हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, बड़कोट, उत्तरकाशी, हिना, गुप्तकाशी, श्रीनगर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में होंगे ऑफलाइन पंजीकरण।

हेली टिकटों की कालाबाजारी रोकी जाएगी।

स्वास्थ्य जांच की होगी समुचित व्यवस्था।

60 प्रतिशत पंजीकरण होंगे ऑनलाइन।

शीतकालीन यात्रा स्थलों का होगा तैयार मास्टर प्लान।

चारो धामों के पुरोहितों ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री के नौ आग्रह बनेंगे विकास का आधार

उत्तराखण्ड के नागरिकों से पांच आग्रह

बोली-भाषा का संरक्षण: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी सहित सभी बोलियाँ बेहद समृद्ध हैं। इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, इसलिए उत्तराखण्ड के लोग आने वाली पीढ़ियों को अपनी बोली-भाषा जरूर सिखाएं।

एक पेड़ मां के नाम: प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी होते हैं। उत्तराखण्ड तो गौरा देवी की भूमि है, यहां हर महिला मां नंदा का रूप है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसके लिए एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण करें। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भी यह आवश्यक है।

स्वच्छ जल: प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में नौला-धारों की पूजा किए जाने की परंपरा है, इसलिए सभी व्यक्ति नौला-धारों को संरक्षित करते हुए, पानी की स्वच्छता के सभी अभियानों को गति देने का प्रयास करेंगे।

गांव से जुड़ाव: उत्तराखण्ड के लोग अपने गांव में आना-जाना बनाते हुए, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। खासकर रिटायरमेंट के बाद गांव में समय जरूर बिताएं, इससे गांवों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे।

तिबारी वाले घरों को संवारें: प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग अपने गांव में पुराने तिबारी वाले घरों को बचाने और संरक्षित करने के लिए भी आगे आएं। पुराने घरों को होम स्टे में बदलकर, आय का साधन बना सकते हैं।

उत्तराखण्ड आने वाले पयर्टकों, तीर्थयात्रियों से चार आग्रह

सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें: पर्यटक के रूप में आप जब भी हिमालय की गोद में जाएं, स्वच्छता को सबसे ऊपर रखें। इस सोच के साथ जाएं कि पहाड़ में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है।

वोकल फार लोकल: पहाड़ों में घूमने फिरने के दौरान वोकल फार लोकल याद रखें, अपनी यात्रा का कम से कम पांच प्रतिशत खर्च स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें।

यातायात के नियम अपनाएं: प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जब भी पहाड़ों पर जाएं, वहां के ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सावधान रहें, हर किसी का जीवन अमूल्य है।

तीर्थों की मर्यादा का पालन करें: धार्मिक स्थलों पर स्थानीय रीति-रिवाजों और नियमों का पालन करते हुए वहां की मर्यादा का ध्यान रखें। इस बारे में उत्तराखण्ड के व्यक्तियों की मदद ले सकते हैं।

मानसखण्ड मंदिरमाला मिशन से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर

मानसखंड के पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

तीर्थाटन, पर्यटन और अध्यात्म के खुले द्वार

मानसखंड मंदिर माला मिशन को मिलेगी वैश्विक पहचान

ऐतिहासिक भ्रमण से स्थानीय लोगों की समृद्धि का मार्ग भी हुआ प्रशस्त

जागेश्वर धाम में तीर्थाटन को मिलेगी गति

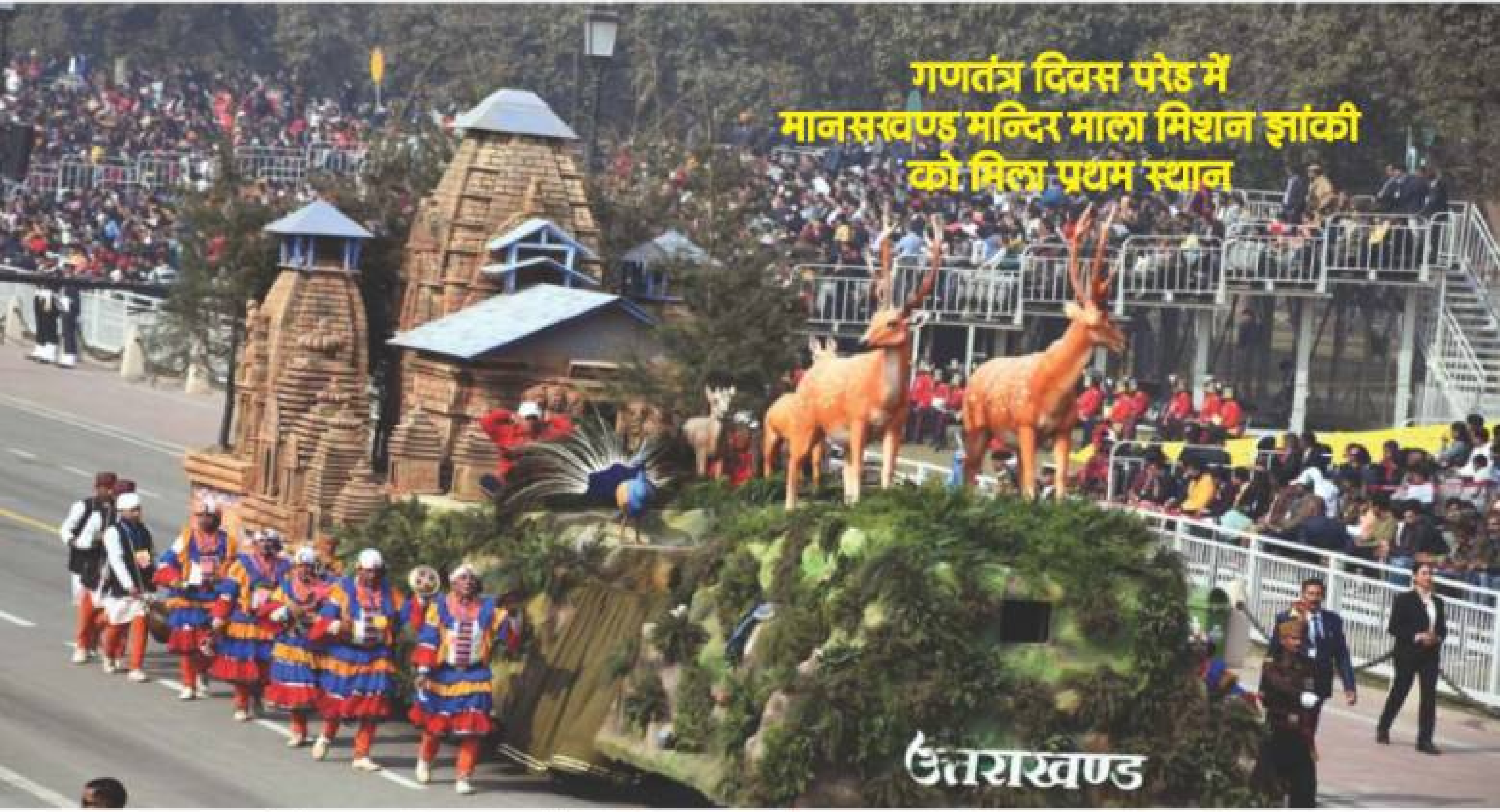

गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित उत्तराखण्ड की झांकी मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पहले नम्बर पर

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च 2023 को उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति 2023 को दी गयी मंजूरी।

2027 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।

उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति 2023 लागू

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति भी तेजी से बढ़ रही लोगों की रुचि। स्थानीय निवासियों को 50% तक सब्सिडी।

• • •

योजना के तहत 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान

• • •

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य में आवेदनों के डिस्पोजल रेट के हिसाब से उत्तराखण्ड देश में पहले नम्बर पर है।

• • •

राज्य में पंप्ड स्टोरेज प्लांट पालिसी भी बनाई गई है। इसमें इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत दिल्ली में हुए रोड शो में जेएसडब्लू ग्रुप ने अपनी रुचि दिखाई थी। कंपनी ने उस समय 15 हजार करोड़ का एमओयू हस्ताक्षरित किया था, जिसमें से 8 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की फ़ाइल स्वीकृति हो चुकी है ।

ऊर्जा क्रान्ति

केंद्रीय पूल से मिलेगी 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली', 'केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया।

प्रदेशवासियों को अब शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिलेगी।

5 नये विद्युत उपकेन्द्रों का कार्य आवन्टित।

180 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को मिलेगी।

पारेषण तंत्र में 780 एम.वी.ए. की क्षमता वृद्धि।

केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समयावधि को भी 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है।

विगत 26 सितंबर को केंद्र की ओर से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए उत्तराखण्ड को आवंटित की गई थी।

आगामी वर्षों में विद्युत मांग की वृद्धि एवं निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं व सौर-ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की निकासी होगी।

16 लाख स्मार्ट मीटरों के स्थापना के कार्य का भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया शुभारंभ।

पिटकुल की ए.डी.बी. वित्त पोषत 05 परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास।

प्रतिमाह 100 यूनिट तक विद्युत खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी धामी सरकार। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। यह सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा।

5 परियोजनाओं में 220 के.वी जी.आई.एस सब स्टेशन सेलाकुई एवं संबंधित लाइन के निर्माण कार्य, 132 के.वी जी.आई.एस सब स्टेशन आराघर एवं संबंधित लाईन के निर्माण कार्य, 132 के.वी जी.आइ.एस सब स्टेशन लोहाघाट एवं संबंधित लाइन के निर्माण कार्य, 132 के.वी जी.आइ.एस सब स्टेशन धौलाखेड़ा एवं संबंधित लाइन के निर्माण कार्य तथा 132 के.वी जी.आइ.एस सब स्टेशन खटीमा द्वितीय और संबंधित लाइन के निर्माण कार्य शामिल हैं।

यूपीसीएल की परियोजनाओं गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र में केन्द्र पोषित आर.डी.एस. एस योजना के अन्तर्गत 16 लाख स्मार्ट मीटरों के स्थापना के कार्य एवं एडीबी द्वारा वाह्य सहायतित उत्तराखण्ड क्लाइमेट रेजिलिएन्ट पावर स्टिम डवलपमेंट प्रोजक्ट के अन्तर्गत देहरादून शहर के प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। इसमें लगभग 977 करोड़ की धनराशि खर्च होगी।

जमरानी बांध परियोजना को मिली स्वीकृति

"जमरानी बांध परियोजना के निर्माण से हल्द्वानी एवं आसपास के क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा तथा विद्युत उत्पादन भी होगा।"

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

सौंग बांध परियोजना से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों की आबादी के लिए पेयजल की होगी आपूर्ति

''बहुउद्देशीय परियोजना चहुंमुखी विकास''

केन्द्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने दी मंजूरी।

परियोजना से विद्युत उत्पादन भी होगा।

सिंचाई एवं पेयजल की समस्या होगी दूर।

किसाऊ जल विद्युत परियोजना से जुड़ी शेष औपचारिकताओं को भी जल्द पूरा कर काम शुरू किया जाएगा।

लखवाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू।

व्यासी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया गया।

उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2024 लागू

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एवं फिल्म निर्माता-निर्देशक श्री प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की

उत्तराखण्ड बन रहा है फिल्म शूटिंग के लिए हॉट स्पॉट

- उत्तराखण्ड को फिल्म शूटिंग हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास।
- फिल्म निर्माण/ऑडियो वीडियो कंटेंट के क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु संबंधित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करना उद्देश्य।
- पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातत्व धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने का लक्ष्य
- क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए ₹ 2 करोड़ की सब्सिडी एवं आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषा की फिल्म के लिए ₹ 3 करोड़ तक की सब्सिडी।
- उत्तराखण्ड में फिल्माई गई क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था।
- उत्तराखण्ड राज्य में शूटिंग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समुचित अनुदान प्रदान करने की योजना।
- स्थानीय बोली और स्थानीय/क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय कलाकारों एवं फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित अनुदान प्रदान करना।
- OTT/Web Series/ TV Serial के निर्माण पर भी सब्सिडी।

फिट इंडिया मूवमेंट

"मोटापा युवाओं सहित सभी आयु समूहों को प्रभावित कर रहा है और मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में अधिक जागरूक हो रहा है।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

फिट उत्तराखड अभियान से मिलेगी नई पहचान

प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाएगा अभियान।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा अभियान।

स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिटनेस को मिलेगा बढ़ावा।

जन-जन तक पहुंचेगा फिट उत्तराखंड का संदेश।

योग, व्यायाम और खेल गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा।

आपदा प्रबन्धन के मोर्चे पर तत्पर सरकार

विश्व आपदा प्रबन्धन सम्मेलन

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, डी.एम.आई.सी.एस. हैदराबाद तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू कॉस्ट) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित।

पद्म विभूषित अमिताभ बच्चन सम्मेलन के ब्रांड एंबेसडर।	दिनांक 28 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2023 तक देहरादून में सम्पन्न हुआ, छठा विश्व आपदा प्रबन्धन सम्मेलन।	आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश एवं दुनियाभर के विशेषज्ञों के बीच हुआ मंथन।
G20 सम्मेलन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डी.आर.आर.) एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है। इस दृष्टि से देहरादून में आयोजित होने वाला छठा विश्व आपदा प्रबन्धन सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण है।	सम्मेलन से पूर्व राज्य भर में आपदा प्रबन्धन के विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। उत्तराखण्ड एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों की आपदा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व स्तर पर किये जा रहे चिन्तन व प्रयासों को मिलेगी गति।	आपदा प्रबन्धन के वैश्विक सम्मेलन से उत्तराखण्ड राज्य में 'सुरक्षित निवेश, सुदृढ़ उत्तराखण्ड' का संदेश देश-विदेश में प्रसारित किया गया। राज्य सरकार इकोलॉजी एवं इकोनॉमी संतुलन बनाकर राज्य में विकास करेगी।

माणा मिशन (28 फरवरी – 2 मार्च)

माणा रेस्क्यू अभियान
मुख्यमंत्री ने स्वयं की निरन्तर मॉनीटरिंग

माणा हिमस्खलन – आपदा से मुकाबला

माणा में श्रमिकों की तलाश के लिए युद्धस्तर संचालित किया गया अभियान

सड़क निर्माण के कार्य कर रहे श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया

दिल्ली से जीपीआर रडार मंगवाई, कंटेनरों को ढूंढने में मिली मदद

जल्द बहाल गई संचार व्यवस्था

सर्च अभियान में रडार और थर्मल इमेजिंग कैमरे जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की ली गई मदद

आपदा प्रबंधन

वनाग्नि पर नियंत्रण

- हर वर्ष 01 अप्रैल को ओण दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत महिलाओं द्वारा एक अप्रैल से पहले खेतों के मेड़ों में उगी कांटेदार झाड़ियों, खरपतवारों को नियंत्रित तरीके से जलाया जाता है।
- वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों में फायर पट्टी का निर्माण कर नियंत्रित फुकान किया जाता है।
- बांज, काफल, उतीश आदि चौड़ी पत्ती प्रजाति के पेड़ों के कटान पर पाबंदी।
- वनाग्नि नियंत्रण के लिए सभी गांवों में महिला मंगल दलों का गठन।
- आग बुझाने में सहयोग करने वाले महिला मंगल दलों को किया जाता है सम्मानित।

प्रवासियों से संवाद

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा "अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन" तथा "प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन" का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी उत्तराखण्डियों द्वारा प्रमुख रूप से पलायन के कारण खाली हुए गांवों को गोद लेकर विकसित करने का संकल्प लिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में 26 देशों के लगभग 60 प्रवासियों द्वारा भागीदारी की गयी। जिनके द्वारा उत्तराखण्ड में विनिर्माण, ऊर्जा, उत्पादन एवं स्टार्ट-अप में निवेश में रूचि दिखाई गयी।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहभागिता से देहरादून में विदेश सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 25 वीं वर्षगाठ को रजत जयंती के रूप में पूरे प्रदेश में वृहद पैमाने पर धूम-धाम एवं हर्षोल्लास के साथ मानाया गया तथा इस अवसर पर कई महानुभावों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।

प्रवासी सम्मेलन

उत्तराखण्ड में मजबूत कनेक्टिविटी

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री का सपना जल्द होगा पूर्ण ।

टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे पर हो रहा है कार्य।

हरिद्वार-देहरादून रेललाइन के दोहरीकरण पर भी भारत सरकार की सहमति।

बेहतर बनायी जा रही है एयर कनेक्टिविटी।

गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे की रखी गई आधारशिला से पर्यटन को लगेंगे पंख।

संचालित होने वाली उड़ान सेवा
1. हल्द्वानी-मुन्स्यारी 2. हल्द्वानी-नैनी सैनी
3. हल्द्वानी-चंपावत 4. जौलीग्रांट-नैनी सैनी
5. पंतनगर-नैनी सैनी

ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन की दूरी 125 किमी है, जिसमें से 104 किमी में 17 टनल बनेंगी। इस रेल लाइन में जिलासू देवप्रयाग सौड़ सबसे लम्बी सुरंग होगी जो लगभग साढ़े चौदह किमी होगी। रेलवे के कार्यों में आधुनिकतम मशीनों का इस्तमाल किया जा रहा है, सभी टनल का कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा।

देहरादून-नैनीताल अल्मोड़ा-बागेश्वर हेलीकॉप्टर सेवा का भी हुआ शुभांरभ।

जी

देहरादून–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए वरदान

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस–वे परियोजना के तीव्र निर्माण कार्य से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ये एक्सप्रेस–वे उत्तराखण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

बेहतर कनेक्टिविटी से अर्थव्यवस्था को मिली तेजी

रेलमार्ग, राजमार्ग के क्षेत्र में प्रगति के साथ ही उत्तराखण्ड में परिवहन में हो रहा है सुधार।
राज्य के पर्यटन और वित्तीय अवसरों को मिल रहा है विस्तार।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना

ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर की ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मील का पत्थर है। 2010-11 में रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यह उपक्रम तीर्थ स्थलों तक आरामदायक, पहुंच को सक्षम बनाने, नए व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस पहल है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाली यह रेलवे लाइन देवप्रयाग, श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे प्रमुख शहरों से गुजरेगी।

सुरंग निर्माण में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि मात्र 44.7 महीनों में 25 किलोमीटर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से खुदाई पूरी कर ली गई है, जिससे देश में सबसे तेज गति से सुरंग बनाने का नया रिकॉर्ड बना है। परियोजना ने 23 अगस्त, 2022 को एक ही दिन में 107.9 मीटर सुरंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

इसके मई 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा की अवधि का मौजूदा 5 घंटे से घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे कर देगा। यह छः लेन वाला राजमार्ग है, जिसे आठ लेन तक विस्तारित किया जाना है। यह न केवल यातायात की भीड़ को कम करेगा, बल्कि यह आवासीय और रिटेल विस्तार को भी बढ़ावा देगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का एक अनोखा पक्ष इसका वाइल्ड लाइफ कोरिडोर है। जो स्थानीय जीवों को बचाने के लिए विकसित किया गया है और यह 12 किमी लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर है।

रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देकर सुगम होगा आवागमन

टनकपुर-देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतरी को दर्शाता है। विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने से यह स्थानीय लोगों और यात्रियों दोनों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान कर रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखण्ड में छः स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। राज्य में रेलवे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को भी सुधारा जा रहा है। देहरादून और आनंद विहार व लखनऊ जैसे अन्य प्रमुख शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत उत्तराखण्ड के रेल नेटवर्क को अपडेट करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। देहरादून से अयोध्या, वाराणसी और काठगोदाम व देहरादून के बीच दिन में सेवा सहित अतिरिक्त वंदे भारत मार्गों की सेवाओं से कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, जिससे यात्रा अधिक कुशल और आरामदायक हो रही है।

एयर कनेक्टिवीविटी

दूर दराज के लिए शुरू हुई हैली सेवा

- देहरादून से उत्तरकाशी और गौचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का किया शुभारंभ।
- राज्य में उड़ान योजना के तहत बन रहे हैं 18 हेलीपोर्ट्स।
- उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना के तहत सहस्त्रधारा (देहरादून) से जोशियाड़ा (उत्तरकाशी) और सहस्त्रधारा (देहरादून) से गौचर (चमोली) के लिए हेलीकॉप्टर सेवा एवं दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का सीएम आवास से वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हवाई सेवाएं, राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं, इसलिए सरकार उड़ान योजना के तहत 18 स्थानों पर हेलीपोर्टस का निर्माण कर रही है।
- दिल्ली-पिथौरागढ़, सहस्रधारा-गौचर, देहरादून-नैनीसैनी, हल्द्वानी-मुन्स्यारी, हरिद्वार-चम्पावत तथा पिथौरागढ़-अल्मोड़ा के मध्य हवाई सेवायें संचालित हैं। देहरादून-नैनीताल, देहरादून-बागेश्वर, एवं देहरादून-मसूरी के मध्य हवाई सेवा भी प्रारम्भ।

रोपवे कनेक्टिवीटी

धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में साबित होगा मील का पत्थर

केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी

- राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में सोनप्रयाग से केदारनाथ (12.9 किमी) तक रोपवे को मंजूरी दी गई है। परियोजना का डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर ₹4,081.28 करोड़ की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा। रोपवे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विकसित करने की योजना है और यह सबसे उन्नत ट्राई-केबल डिटेचेबल गोंडोला (3एस) तकनीक पर आधारित होगा। इसकी डिजाइन क्षमता 1,800 यात्री प्रति घंटे प्रति (पीपीएचपीडी) होगी, जो प्रतिदिन 18 हजार यात्रियों को ले जाएगी।
- यह रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए वरदान होगी, क्योंकि यह पर्यावरण-अनुकूल, आरामदायक और तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे से घटकर लगभग 36 मिनट कर देगी। रोपवे परियोजना निर्माण और संचालन के साथ-साथ आतिथ्य, यात्रा, खाद्य और पेय पदार्थ (एफ एंड बी) और पर्यटन जैसे संबद्ध पर्यटन उद्योगों में पूरे वर्ष रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगी।
- राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य में गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी (12.4 किमी) तक रोपवे परियोजना के विकास को भी दी मंजूरी ।
- गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना का डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजीगत लागत ₹ 2,730.13 करोड़ है। वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी की यात्रा गोविंदघाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और इसे पैदल, घोड़ा-खच्चर, पालकी से किया जाता है। प्रस्तावित रोपवे की योजना हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है और यह गोविंदघाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच हर मौसम में अंतिम मील की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।

- ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र के ढांचागत विकास पर जोर दिया गया तथा जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का स्थाई विकास कर पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने की दिशा में हो रहा है प्रयास।
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट गांव का किया जा रहा है सुनियोजित विकास।
- गांव में पॉलिहाउस लगाकर यूरोपियन वेजिटेबल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- गांव में मसाला चक्की लगाने के साथ डेयरी पर काम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य जांच के लिए गांव में नियमित शिविर लगाए जा रहे हैं।
- सारकोट गांव में सोलर लाइट लगाकर गांव को किया गया है रोशन।

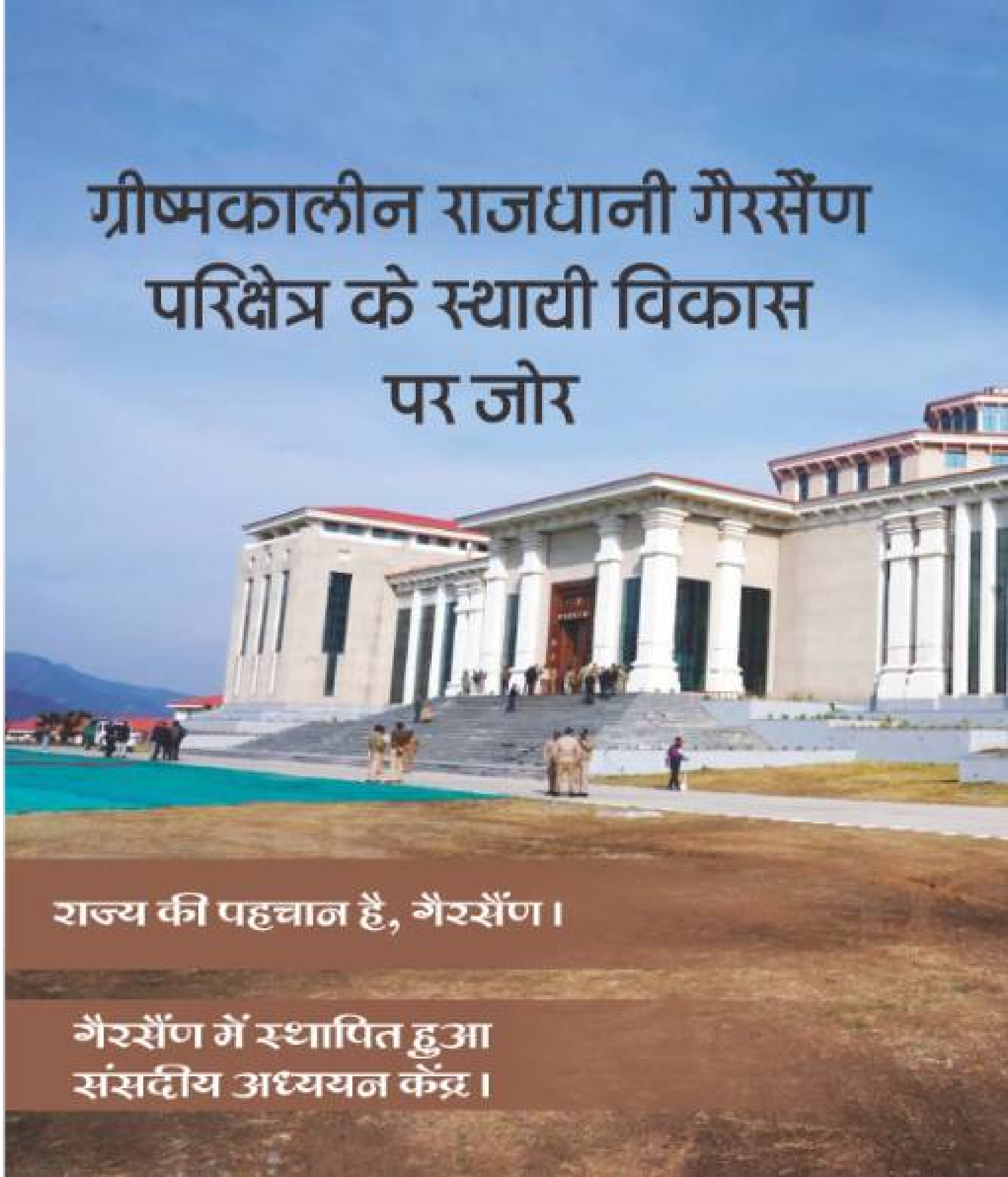

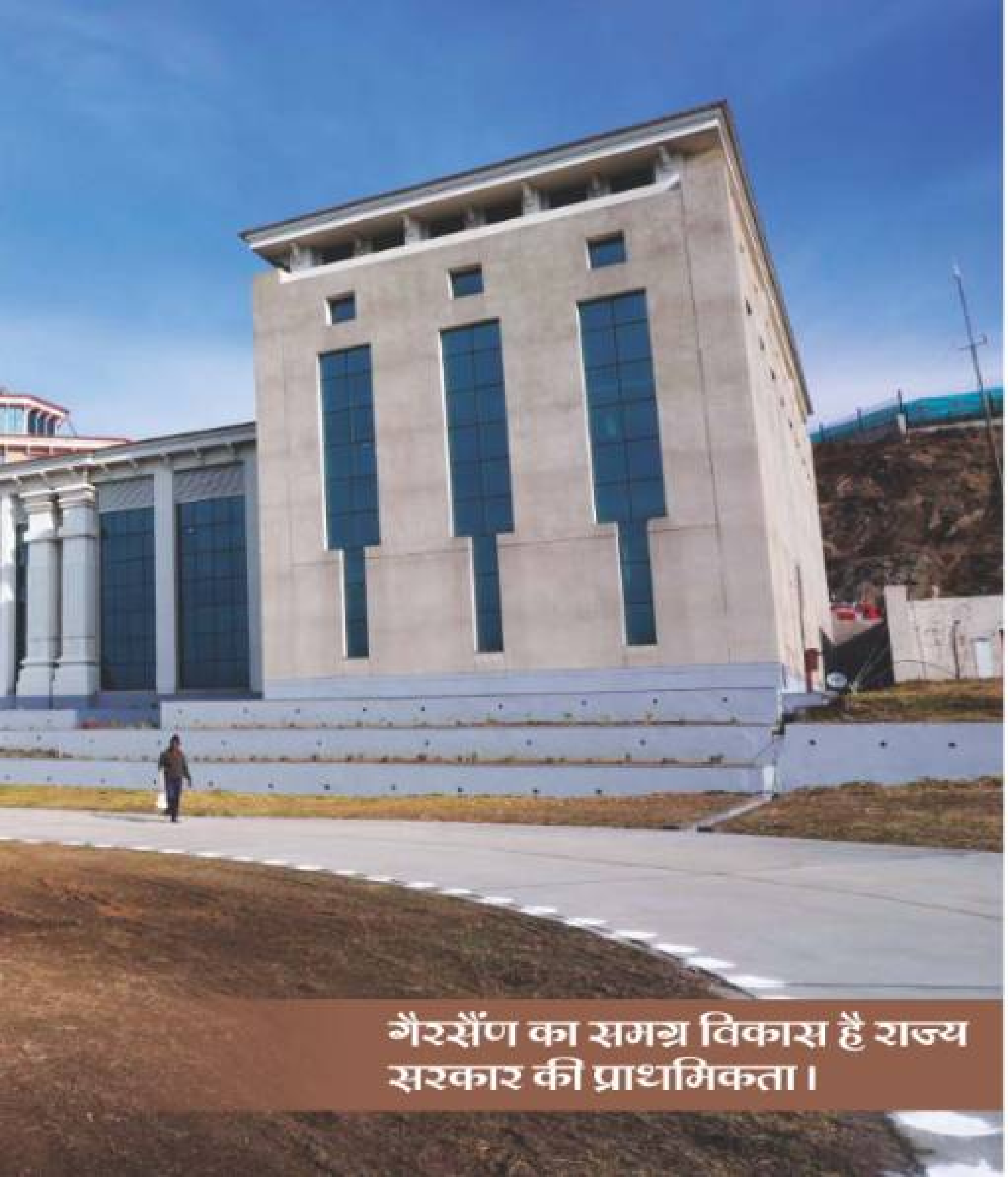

- मशरूम उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गैरसैंण ब्लाक के आदिबद्री, खेती, मालसी और थापली गांव का चयन करते हुए यहां पर किसानों को शतप्रतिशत अनुदान देकर मशरूम टनल बनाई गई और किसानों को मशरुम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया।
- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने की दिश में पहले चरण में राजकीय इंटर कॉलेज भराड़ीसैंण को आदर्श विद्यालय बनाने का काम तेजी से चल रहा है।
- गैरसैंण नगर क्षेत्र में जाम की समस्या को दूर करने के लिए बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग।
- भराड़ीसैंण में मां भराड़ी देवी का बनेगा भव्य मंदिर।

स्वस्थ उत्तराखण्ड

- स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल सुविधा भी शुरू।
- मरीजों को घर बैठे भी मिल रही है विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं ।
- आयुष्मान योजना बनी जीवनदायिनी।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 57 लाख से अधिक लाभार्थियों के बने आयुष्मान कार्ड और करीब 13 लाख लोगों को मिला मुफ्त उपचार।
- आयुष्मान कार्ड धारकों को देश के 22 हजार से अधिक नामी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक के निशुल्क इलाज की मिली सुविधा।
- मरीज निजी अस्पतालों में भी बिना रेफरल के ही सीधा करा रहे हैं इलाज।
- 9.60 लाख बुजुर्गों को मिलेगा अलग से मुफ्त इलाज।
- तीन साल में खुले दो नए मेडिकल कॉलेज।
- वर्ष 2022 में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हो चुका है शुरू।
- जबकि इसी सत्र से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में भी शुरू होने जा रही है पढ़ाई।
- दोनों कॉलेजों की कुल 200 नई सीटें जुड़ने से उत्तराखंड में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर हुई 625 ।
- हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पहले से ही हो रहा है संचालित।
- कैंसर के उपचार की अब उत्तराखण्ड में भी होगी शुरूआत । बागेश्वर, चम्पावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में होगी कैंसर केयर यूनिट की स्थापना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तैयार किया गया है प्रस्ताव।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को मिली नई ऊँचाई

उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय में 11.33% बढ़ोत्तरी का अनुमान।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखण्ड की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,74,064 होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.33% अधिक है।

भारत सरकार के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,00,162 अनुमानित है जो कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाता है।

बजट 2025–26

प्रदेश की आर्थिक दिशा, नीतियों और सामाजिक कल्याण की पहलों को आकार देने का एक शक्तिशाली साधन है।

- **नमो का प्रथम बिन्दु N** अर्थात् नवाचार के प्रतीक अनेक बिन्दु जैसे परिवार पहचान पत्र, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, फायर हाइड्रेन्ट मशीन, स्मार्ट मीटर, साईस सेन्टर, स्मार्ट क्लास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

- **नमो के दूसरे बिन्दु A** अर्थात् आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के लिए बजट में 'सप्तऋषि' की अवधारणा दी गयी है: कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसरंचना, संयोजकता, पर्यटन तथा आयुष। ये 'सप्तऋषि' आधुनिक उत्तराखण्ड के हमारे ग्रोथ इंजन हैं।

- **नमो के तीसरे बिन्दु M** अर्थात् महान विरासत के संरक्षण के लिए अनेक पहल सरकार ने की है :-

शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाना, गोविंद घाट से घांघरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह, बिढौरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति आदि।

हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास, शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास, कांवड़ मेले के आयोजन, अर्द्धकुम्भ मेले की प्रारम्भिक तैयारी, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु विभिन्न मेलों के आयोजन, संस्कृत पाठशालाओं व विश्वविद्यालय को अनुदान आदि हेतु बजट प्रावधान किये गये हैं।

संस्कृति के पावन मूल्यों की रक्षा, प्रदेश का भविष्य उज्जवल करना तथा विकास भी और विरासत भी के सिद्धान्त पर अडिग रहना, यह कार्यनीति है। इसका परिलक्षण इस बजट में होता है।

- **नमो के चौथे बिन्दु O** अर्थात् ओजस्वी मानव संसाधन के लिए हमारी पहल :-

उत्तराखण्ड वेंचर फंड की स्थापना, उद्यमिता को प्रोत्साहन, कृषकों को प्रोत्साहन, खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, देवभूमि उद्यमिता योजना, छात्रवृत्तियाँ, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन आदि।

इस बजट में समावेशी व समग्र विकास के दृष्टिकोण से ज्ञान (GYAN) अर्थात् गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है।

इकॉलोजी, इकोनामी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल व इन्क्लूजिव डेवलवपमेंट तथा एकाउन्टेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए कार्य पर फोकस।

सरलता, समाधान और निस्तारीकरण द्वारा विकास के अवरोध दूर करने का प्रयास।

यह बजट NAMO (नमो) नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है।

सशक्त उत्तराखण्ड @25
गेम चेंजर योजनाएं

कृषि

ई-रूपी योजनाः यह कैश का डिजिटल फॉर्म है। बुनियादी ढांचे जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम सुरक्षा प्रणाली विकसित होगी। दूरस्थ गांवों तक वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। राजस्व बढ़ेगा, कागज व धातु का उपयोग कम होगा। इसके लिए बजट में 25 करोड़ दिए गए हैं।

पशुपालन

वाइब्रेंट विलेज योजनाः स्थानीय उत्पादों जैसे जीवित बकरी, भेड़, कुक्कुट, ट्राउट मछली की आपूर्ति आईटीबीपी को देकर हर साल 20 करोड़ व्यवसाय। दूसरी, ग्राम्य गो सेवक योजना में छह जिलों में 54 गो सेवकों को मान्यता। ये सार्वजनिक स्थानों पर घूमते निराश्रित नर गोवंश की संख्या में कमी पर कार्य करेंगे।

मत्स्य

फ्लोट फार्मिंग योजनाः राज्य स्तरीय एकीकृत एक्वा पार्क, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत मत्स्य हैचरी का पीपीपी मोड पर संचालन। इससे आय में बढ़ोतरी होगी।

वन

इको-टूरिज्म और गैर प्रकाष्ठ वन उपज का विकास, हर्बल एवं इको-टूरिज्म परियोजना। हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर को छोड़कर बाकी जिलों में योजनाएं चलेंगी।

शहरी विकास

100 करोड़ से राज्य में 100 नए पार्कों का निर्माण। एआई के माध्यम से 275 करोड़ से स्ट्रीट लाइट का मैनेजमेंट।

बद्री-केदार मंदिर समिति

बदरी-केदार मंदिर समितिः शीतकालीन चारधाम यात्रा योजना शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्मी हस्तियों, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों व विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त महानुभावों से संपर्क कर उन्हें ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा। इनकी सेवाएं भी ली जा सकती है।

सगंध पौध केंद्र

महक क्रांति योजनाः यह योजना 2035 तक चलेगी। मुख्य लक्ष्य ऐरोमा वैली की स्थापना, 118 करोड़ के बजट से सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा, किसानों का आय में वृद्धि, सुगंधित तेलों व उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का काम होगा।

उद्यान

एप्पल, मिशन, नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत क्लस्टर पॉलीहाउस की स्थापना। ये योजनाएं बागवानी के विकास का नई दिशा देंगे।

ग्राम्य विकास

हाउस ऑफ हिमालयाज योजनाः इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग

पेपरलैस रजिस्ट्रेशन

पंचायती राज

ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधा, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स आधारित थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण।

श्रम

श्रम पोर्टल तैयार करना। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर को शून्य बाल श्रम क्षेत्र बनाना।

पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024, स्थायी निवासियों को पांच करोड़ तक पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।

परिवहन

पीएम ई-बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बस संचालन। चारधाम यात्रा मार्ग पर 28 ई-चार्जिंग स्टेशन, जो 856 किमी मार्ग को कवर करेंगे। 7-75 करोड़ खर्च होगा। दूसरे चरण में 41 चार्जिंग स्टेशन, तीसरे चरण में 70 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।

माध्यमिक शिक्षा

प्रोजेक्ट प्रज्ञा एवं वैश्विक संस्थाओं के सहयोग से हॉस्पिटैलिटी एंड कलिनरी क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण।

उच्च शिक्षा

समर्थ ई-गवर्नमेंट पोर्टल फॉर डिजिटलाइजेशन व देवभूमि उद्यमिता योजना।

ऊर्जा

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना।

सिंचाई

बांध, बैराज निर्माण। स्लोप स्टेबलाजेशन। स्टॉम वाटर ड्रेनेज।

कौशल विकास

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। स्किल सेंसस के लिए 50 लाख। नियोक्ता व नौकरी वालों के लिए एकीकृत पोर्टल योजना के लिए 50 लाख, सेवायोजना कार्यालयों का पुनर्गठन के लिए दो करोड़। लक्षित समूह की नौकरी के लिए पांच लाख का प्रावधान।

तकनीकी शिक्षा

ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं रोजगार योजनाएं।

नियोजन

सेतु आयोग का गठन, यूआइआइडीबी गठन, सर्विस सेक्टर नीति का गठन, परिवार पहचान पत्र।

चाय बोर्ड

टी टूरिज्म योजना, होम स्टे योजना।

स्वास्थ्य

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ परामर्श, द्वार पर निदान, आत्मनिर्भर मेडिसिटी को बढ़ावा। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली व नर्सिंग छात्रों का कौशल विकास।

लोनिवि

रिस्पना-बिंदाल पर चार लेन एलिवेटेड सड़क निर्माण। दून-मसूरी कनेक्टिविटी, देहरादून रिंग रोड, यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी।

तीन नये आपराधिक कानून किये गये लागू

भारतीय न्याय संहिता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम-2024: राज्य में हड़ताल, बन्द, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जायेगी तथा इनमें से किसी की मृत्यु होने पर कानूनी धारायें लगाये जाने के साथ ही आरोपितों को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अंतर्गत बच्चों/गुमशुदाओं को ट्रैस किया जा रहा है तथा ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुक्त कराकर बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया जा रहा है।

साइबर क्राइम से सम्बन्धित प्रकरणों में सहायता हेतु जनता के लिए साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 जारी किया गया है। जन जागरूकता हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैनर होर्डिंग, पम्पलेट्स आदि के माध्यम से साइबर सुरक्षा टिप्स आमजन को साझा किये जा रहे हैं।

यातायात प्रबन्धन के क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा हेतु Map my India एवं Google Map के साथ हुए समझौते के आधार पर राज्य की Real Time Traffic Advisory की सुविधा Mapple/Google Map के माध्यम से आमजन को प्रदान की जा रही है।

कारागार विभाग द्वारा उत्तराखण्ड बन्दी की मृत्यु पर विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नीति-2024 लागू की गयी है।

कौशल विकास से सेवायोजन तक

सहसपुर तथा देहरादून स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को स्किल हब के रूप में विकसित करते हुए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के साथ-साथ मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की गई।

राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टैक्नालॉजी प्रा.लि. के माध्यम से उन्नयन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

सेवायोजन कार्यालयों के अन्तर्गत संचालित कुल 16 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को समूह 'ग' परीक्षा में सफलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

खेत, खलिहान और खुशहाली

पॉलीहाउस के लिए नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. योजना में क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए 50 से 500 वर्ग मी. आकार के छोटे पॉलीहाउस स्थापना के लिए 80% की सब्सिडी है।

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना का संचालन किया जा रहा है।

राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिक को बढ़ाने में सहायक होंगे।

श्री अन्न (मिलेट) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2021-22 में मंडुआ समर्थन मूल्य कुल ₹ 2500 प्रति कुंतल था, जो वर्ष 2024-25 में ₹ 4200 प्रति कुंतल हो गया है। इस तरह दो साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68 प्रतिशत बढ़ गया है। अन्नदाता प्रेरित होकर मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से भी मंडुआ उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

समाज कल्याण: संवेदनशील सरकार

सामाजिक न्याय और सबका विकास

समाज कल्याण विभाग द्वारा दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों को विश्व दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार के रूप में दी जानी वाली धनराशि को ₹ 5000 से बढ़ाकर ₹ 8000 की गयी है एवं कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि को ₹ 3500 से बढ़ाकर ₹ 7000 किया गया है।

जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय, उत्तराखण्ड द्वारा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों में खेल के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय जनजाति युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया।

जनपद के दूरस्थ स्थानों में निवासरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को शहरी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा नि:शुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

एक पेड़ माँ के नाम # अभियान

वन एवं पर्यावरण का किया गया संरक्षण

वृहद वृक्षारोपण के अंतर्गत 30250.23 हे. में 206.43 लाख पौध रोपित की गई

वर्ष 2023 में ईको टूरिज्म नीति घोषित की गई। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं इससे अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु 18 ईको टूरिज्म गन्तव्यों को विकसित किया जा रहा है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष व जंगली जानवरों से खेती की रक्षा हेतु बायोफेंसिंग, बन्दरों का वन्ध्याकरण, फारेस्ट लैण्डस्केप रेस्टोरेशन सहत वनों के घनत्व में वृद्धि हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण की रोक-थाम व प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल के प्रयोग को पूर्ण रूप से बन्द किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के लगभग 14 लाख परिवारों को प्रति राशनकार्ड ₹ 8 प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रतिमाह 1 कि.ग्रा. नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र-विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के सहयोग से राज्य में 21 ग्रेन एटीएम स्थापित किय गये हैं, यहां से उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अन्त्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय राशनकार्डधारक परिवारों को तीन गैस सिलेण्डर रिफिल नि:शुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित कर दिया गया है।

जून, 2024 में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारम्भ किया गया योजनान्तर्गत कुल 13,98,816 राशन कार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री अन्त्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना के अन्तर्गत तीन (3) गैस सिलेन्डर रिफिल की नि:शुल्क सुविधा का लाभ 1,84,108 अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 12,14,708 प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों को 5 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रति माह तथा अन्त्योदय के 1,84,108 राशन कार्डधारकों को 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत 9,94,993 कार्डधारकों को 7.5 किलो ग्राम चावल ₹11 प्रति किलो ग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है।

परिवहन

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में वी.एल.टी. (Vehicle Location Tracking) डिवाइस संस्थापित की जा रही हैं। उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसके द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैंक एण्ड सॉफ्टवेयर बनाया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नियमावली प्रख्यापित की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर कैबिनेट की मुहर

- बार-बार अपराध करने वालों पर होगी कार्यवाही।
- दुर्घटना रोकने के लिए ली जाएगी AI की मदद।
- फिटनेस ऑटोमेशन का सिस्टम होगा विकसित।
- क्रश बैरियर्स, पौध रोपण पर होगा जोर।

सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर या दो अंगों की पूर्ण हानि होने पर या दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करते हुए मृतक आश्रितों को ₹ 2 लाख की राहत राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में Speed Limiting Device की अनिवार्यता के फलस्वरूप वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किये जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत स्पीड रडार गन युक्त ए.एन.पी.आर. (Automated number plate recognition) कैमरों की स्थापना की जा रही है।

शिक्षा

- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना कक्षा 6 से स्नातक तक लागू करने का निर्णय।
- सरकारी स्कूल के सभी छात्र-छात्राओं को किताब के अतिरिक्त कॉपी नोट बुक देने का फैसला।
- विज्ञान विषय में दी जा रही है द्विभाषी पुस्तकें।
- अशासकीय स्कूलों में भी शामिल की गयी पाठ्य-पुस्तक योजना।
- हर ब्लॉक में मेधावी छात्र-छात्राओं को भारत भ्रमण का अवसर।
- शिक्षकों के रिक्त पदों पर हो रही है बम्पर भर्ती।
- मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 6-12 तक मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना लागू।

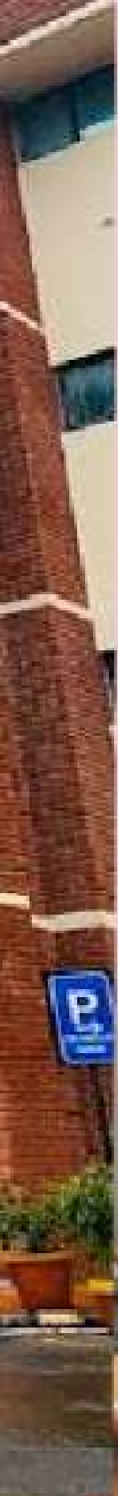

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किये जाने तथा समय से परीक्षा का आयोजन किये जाने हेतु समर्थ पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। यह पोर्टल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाते हुए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु दृढ़ संकल्पित है।
- राजकीय महाविद्यालयों/राज्याधीन विश्वविद्यालय के अधिकतम 5 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रतिष्ठित संस्थानों में 1 वर्ष के लिए स्नातकोत्तर स्तर (मास्टर डिग्री) के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री रोविनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है।

- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) बैंगलौर द्वारा दून विश्वविद्यालय को 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है। 'ए' ग्रेड से प्रत्यायित दून विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय है।
- शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के अन्तर्गत विज्ञान विषय वाले इण्टर कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को प्रयोगात्मक सुविधा हेतु Lab On Wheels (चलती-फिरती प्रयोगशाला) की योजना का संचालन राज्य के 4 जनपदों चम्पावत, अल्मोड़ा, पौड़ी एवं देहरादून में किया जा रहा है।
- राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त (अशासकीय) विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध करायी गयी हैं।
- शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाये जाने हेतु एवं छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्या समीक्षा केन्द्र को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है।

नारी शक्ति

महिला की शान सुरक्षा और सम्मान

- लखपति दीदी योजना बना महिलाओं की आर्थिक समृद्धि का आधार।
- पहले 2 बच्चों तक महालक्ष्मी किट योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला।
- कोरोना में निराश्रित हुए बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना।
- मुख्यमंत्री महिला सारथी योजना को किया गया पायलट योजना के तहत आरम्भ।
- मिनी आंगनवाड़ियों को दिया गया पूर्ण आंगनवाड़ी का दर्जा।
- महिला कल्याण के तहत अंतोदय परिवार का 3 मुफ्त सिलेंडर का तोहफा।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में गत् वर्ष हुए निवेश प्रस्ताव के आधार पर ऊर्जा, आवास, विनिर्माण, आधारभूत संरचना एवं पर्यटन आदि के क्षेत्र में निवेश की ग्राउंडिंग तेजी से हो रही है।

स्टार्टअप को इन्क्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'यू-हब' नाम से आइटी पार्क देहरादून में इन्क्यूबेटर की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य में 73000 वर्ग फीट का इन्क्यूबेशन क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा।

खुरपिया फार्म (किच्छा) में 1002 एकड़ भूमि पर भारत सरकार की अमृतसर कोलकता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC) स्वीकृत किया गया है। इस प्रोत्साहन के साथ ही राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर और अधिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 168 स्टार्टअप तथा 15 इन्क्यूबेटर को मान्यता प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा राज्य के 1196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में सम्मिलित है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को Plug and Play Model पर उद्यम स्थापना हेतु स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है।

रोजगार का आधार

ऊर्जा–जल विद्युत परियोजनाएं

ऊर्जा विभाग द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड एवं टी.एच.डी.सी. का संयुक्त उपक्रम का गठन कर कुल 489 मे.वा. क्षमता की 03 जल विद्युत परियोजनाएं एवं कुल 1230 मे. वा. क्षमता की 02 पम्प स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित की गयी हैं।

हिमाच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपयोग 200 यूनिट तक है, को लागू विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है। अन्य क्षेत्रों के घरेलू क्षेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपयोग 100 यूनिट तक है, को भी विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य पी.एम.-जनमन-योजना के अन्तर्गत बुक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित घरों को ग्रिड के माध्यम से निःशुल्क विद्युतीकृत कर इस कार्य में देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हुआ है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
राज्य सरकार के प्रयासों से लगभग 600 मेगावाट
सौर ऊर्जा उत्पादित की जा रही है।

सौरसमृद्ध उत्तराखण्ड

वीरभूमि को प्रणाम

वीरांगनाओं को निःशुल्क सफर का निर्णय।

शहीद आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था को और अधिक किया गया सरल और व्यापक।

जल्द ही शहीद सैनिक आश्रितों का आर्थिक अनुदान 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जायेगा।

वीरता पदक विजेताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 लाख से 30 लाख की गई।

मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा की गई सम्पन्न।

उत्तराखण्ड जनजातीय महोत्सव–2025

उत्तराखण्ड जनजातीय महोत्सव-2025 कार्यक्रम उत्तराखण्ड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार-2025 से सम्मानित हुए लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी एवं श्री किशन महीपाल।

जनजातीय शोध संस्थान के ढाँचें को स्वीकृति प्रदान करने कि घोषणा मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना के संचालन के लिये प्रतिवर्ष ₹ 1 करोड़ की धनराशि की जाएगी प्रदान।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को 3 गुना बढ़ाया गया है। जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन- धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संवंधित योजनाओं के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार भी उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून एवं देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। यूसीसी से सभी जनजातीय समाज के लोगों को बाहर रखा गया है।

सतत् विकास का संकल्प

पर्यटन

- विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखण्ड के चार गांवों - सूपी (बागेश्वर), गुंजी (पिथौरागढ़) एवं जखोल व हर्षिल (उत्तरकाशी) को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

सिंचाई

- इस वर्ष गोला नदी जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना एवं सौंग नदी पर सौंग बाँध पेयजल परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा रानीखेत शहर की पेयजल आपूर्ति के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण गगास बैराज का निर्माण पूर्ण किया है।

प्रवासी सम्मेलन

- जनवरी, 2025 में देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन उत्तराखण्ड की अभिनव पहल रही है। यह सम्मेलन, विदेशों में रहने वाले उत्तराखण्ड के प्रवासी भाई-बहनों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल रही। प्रवासियों द्वारा "गाँव को गोद लें (एडोप्ट ए विलेज)" की अवधारणा हमारे गाँवों के लिए एक नई प्रेरणा है।

आर्थिक उन्नति

- नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी इंडेक्स) 2023-24 की रिपोर्ट में देश में उत्तराखण्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहना राज्यवासियों के लिए गौरवान्वित होने का अवसर है। शीर्ष स्तर पर बने रहना एक चुनौती भी है। इसीलिए इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि सभी विभाग अपने से सम्बन्धित इंडीकेटर्स में शीर्ष प्रदर्शन करें। इस हेतु मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जा रहा है
- औद्योगिक क्षेत्र में भी राज्य की उपलब्धियों को भारत सरकार ने सराहा है। राज्य को "लाजिस्टिक्स इज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स" (लीड्स), पहल में "टॉप एचीवर्स" के रूप में मान्यता दी गई है। यह सम्मान राज्य में लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है
- स्टार्ट-अप इंडिया राज्य में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को "लीडर" श्रेणी तथा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाईन सिंगल विंडो के लिए "टॉप एचीवर्स" श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धियां औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- आई.सी.आर.टी. इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार-2024 के संस्करण में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड को "सिल्वर अवॉर्ड" प्रदान किया गया है।

स्टेट मिलेट् मिशन से जैविक खेती को मिली पहचान

- श्री अन्न (मिलेट) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडुआ समर्थन मूल्य कुल रू. 2,500 प्रति कुंतल था, जो 2024-25 में ₹ 4,200 प्रति कुंतल हो गया है। इस तरह दो साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68 प्रतिशत बढ़ गया है अन्नदाता प्रेरित होकर मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से भी मंडुआ उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे।

हाउस ऑफ हिमालयाज योजना

- "हाउस ऑफ हिमालयाज" योजना के अन्तर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय-जड़ी-बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

उद्योग

- सरकार द्वारा स्टार्ट-अप व एम.एस.एम.ई. अनुकूल इको सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। सिडकुल द्वारा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।
- उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिये हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में ₹ 194 करोड़ की लागत से फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमी मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। फ्लैटिड फैक्ट्री, सेलाकुई एवं पंतनगर की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
- पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योगों द्वारा वेयर हाउस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
- काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर तथा 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है।
- सितारगंज फेज-2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है।
- 80 एकड़ भूमि में खानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का कार्य गतिमान है।
- इस बजट में औद्योगिक परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु ₹ 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु ₹ 35 करोड़ तथा प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटरप्रीनियोरशिप योजना हेतु ₹ 30 करोड़ सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

आयुष

उत्तराखण्ड योग व आयुष की भूमि है। इसी आलोक में "आयुष" को राज्य सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। आयुर्वेद परम्परागत रूप से देवभूमिवासियों के लिए एक जीवन शैली है। राज्य सरकार विकास भी विरासत भी मंत्र के साथ आयुष का परम्परागत ज्ञान आमजन तक तथा देश व विदेश में पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024 का अभूतपूर्व आयोजन किया था। आयुष और योग के प्रचार व प्रसार द्वारा राज्य सरकार फिट इंण्डिया मूवमेंट के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी समुचित परिवेश के निर्माण के दायित्व का निर्वहन कर रही है।

- आयुष, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए उत्तराखंड आयुष नीति लागू की जा चुकी है।
- प्रदेश को वैश्विक योग गंतव्य के रूप में स्थापित किए जाने हेतु देश की प्रथम योग नीति प्रख्यापन की प्रक्रिया गतिमान है।
- योग विधा को सुदृढ़ किए जाने हेतु आयुष विभाग के अन्तर्गत ही योग निदेशालय स्थापित किया जाना विचारधीन है।
- प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (एन.ए.बी.एच.) के माध्यम से प्रत्यायन करवाया जा रहा है। प्रदेश में संचालित होम स्टे को वैलनेस सेवाओं के साथ संयोजित किया जा रहा है।
- एक समृद्ध विरासत की दृष्टि से धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन में अग्रणी हैं। हमारे पास योग और आयुर्वेद की स्वस्थ परंपरा तथा गुरुकुल और ऋषिकुल जैसे ऐतिहासिक संस्थान है।
- राज्य में योग को व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित कर पर्यटन, विरासत एवं स्वस्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं।

कार्मिक कल्याण

- राज्य के राजकीय कार्मिकों को पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
- हमारी सरकार द्वारा एलटीसी हेतु न्यूनतम अवकाश की अवधि 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है तथा लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी-तीन, लेवल 6 से 9 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी-दो तथा लेवल 10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों हेतु रेल यात्रा में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा हवाई यात्रा की अनुमन्यता प्रदान की गयी है।
- जून और दिसम्बर माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन में वित्तीय लाभ प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि (नोशनल) अनुमन्य की गई है।
- राजकीय वाहन चालकों को प्रतिवर्ष ₹ 3,000 वर्दी भत्ते की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

उत्तराखण्ड

वन

- नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। इसके लिये सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें।
- वैज्ञानिक आधार पर जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए तेजी से कार्य किये जाए। इसके लिए यूकॉस्ट, यूसर्क एवं जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिए कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए।
- जिन नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए अभी तक चिन्हित किया गया है, उनका बेस लाइन डाटा भी बनाया जाय। इनके पुनर्जीवीकरण के लिए लघुकालिक और दीर्घकालिक योजना के साथ कार्य किए जाए।
- वर्षा जल संचय की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई गई नीति का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करवाया जाए।
- वनाग्नि से संभावित क्षेत्रों में वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए ऐसे क्षेत्रों में नमी संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए वन विभाग पूरी योजना बनाकर कार्य करे। जो जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए सुनियोजित तरीके से कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जाएं।
- चाल-खाल और अमृत सरोवरों के निर्माण में और तेजी लाई जाय। शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण संचय और संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य किये जाएं।
- आगामी हरेला पर्व से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। यह अभियान एक माह तक चलाया जाए। फलदार और छायादार वृक्षों का अधिक रोपण किया जाए। वृक्षारोपण के साथ उनका संरक्षण सबसे अधिक जरूरी है, इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- न्याय पंचायत स्तर, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान के तहत फलदार पौध वितरित किए जाएं।
- इस अभियान को न्याय पंचायत स्तर तक विस्तार किया जायेगा। वन विभाग द्वारा सेक्टर बनाकर वृक्षारोपण किया जायेगा।
- पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। जल संचय और संरक्षण के परंपरागत तरीकों पर नियमित कार्य करना होगा। इस अभियान को जन अभियान बनाना जरूरी है।

महिला सशक्तिकरण

- प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और जागरूकता अभियान, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना एवं महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देकर नारी कल्याण के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।
- सतत् विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) इंडीकेटर्स के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव एवं लिंग अनुपात में सुधार के लिए सरकार गंभीरतापूर्वक प्रयत्न कर रही है।
- 'वर्क पॉपुलेशन रेशियों' में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राज्य में महिलाओं के कार्य बल में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार 6 माह से 6 वर्ष के शिशुओं की उचित देखभाल, सुरक्षा, पूरक पोषण, विकास, निगरानी, स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल-पूर्व शिक्षा, आंगनबाड़ी-सह-क्रैच केन्द्रों मे उपलब्ध करायी जा रही है। प्रथम चरण में दिनांक 7 अक्टूबर, 2024 को जनपद देहरादून में सत्रह, हरिद्वार में तीन, टिहरी गढ़वाल में एक, पौढ़ी गढ़वाल में एक तथा ऊधमसिंहनगर में बारह आंगनबाड़ी-सह-क्रैच केन्द्रों का शुभारम्भ किया गया है।
- राज्य के 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी में उच्चीकृत किया गया है। राज्य में 3,940 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।
- नारी कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किये गए हैं। जेंडर बजट में लगभग 16.66% की वृद्धि के साथ इस बजट में लगभग ₹ 16,961.32 करोड़) का प्रावधान किया है।
- नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभग ₹ 157.84 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनान्तर्गत लगभग ₹ 21.74 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गत लगभग ₹ 29.91 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभग ₹ 22.62 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभग ₹ 18.68 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभग ₹ 13.96 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत ₹ 14 करोड़, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु ₹ 8 करोड़, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹ 5 करोड़, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लगभग ₹ 3.76 करोड़, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु ₹ 5 करोड़, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ₹ 5.00 करोड़, राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग ₹ 14.13 करोड़ तथा मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजनान्तर्गत ₹ 2 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

पशुपालन

- पशुपालन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की 22 घोषणाओं के सापेक्ष 16 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 02 घोषणाएं अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण स्थानान्तरित की गयी है तथा 04 घोषणाओं में कार्यवाही गतिमान हैं।
- मा० मुख्यमंत्री जी के वर्तमान कार्यकाल में स्वरोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत **3331** लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- राज्य के पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु उन्हें गाय, भैंस, खच्चर, बकरी, भेड़ तथा कुक्कुट पालन हेतु बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत 1962 टोल फ्री नंबर के माध्यम से दिनॉक 16 नवम्बर, 2022 से प्रदेश भर में 60 मोबाइल वेटरनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है।
- श्यामपुर-ऋषिकेश में स्थापित देश की प्रथम लिंग वर्गीकृत प्रयोगशाला में उत्पादित वर्गीकृत वीर्य से 90 प्रतिशत से अधिक बछिया संतति की उत्पन्नता तथा वर्गीकृत वीर्य को बढ़ावा देने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिडोज अनुदान राशि ₹ 500.00 कर दी गई है।

नई योजना

- **गोट वैली परियोजना (Goat Valley)** दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गोट वैली योजना का शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य क्लस्टर-आधारित बकरी पालन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अन्तर्गत पशुपालन, ग्रामीण विकास, और सहकारी विभागों से संबंधित योजनाओं को संयोजित कर क्लस्टर-आधारित बकरी पालन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद में एक गोट वैली स्थापित की गई है। प्रत्येक गोट वैली में न्यूनतम 100 बकरी पालकों को सम्मिलित कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में ₹ 30,000 एन.सी.डी.सी. से ऋण एवं ₹ 63000 राज्य सेक्टर योजना से अनुदान प्रस्तावित है।
- 13 जनपदों के अन्तर्गत 18 क्लस्टर गोट वैली स्थापित की गयी हैं, जिसके अर्न्तगत वर्तमान तक 3822 लाभार्थियों को चयनित किया गया है तथा 2574 लाभार्थियों को एन.सी.डी.सी. का ऋण वितरित किया गया है। योजनार्न्तगत लगभग 35737 बकरियाँ वितरित की जा चुकी हैं।
- **कुक्कुट वैली की स्थापना**-ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पलायन की रोकथाम, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने आदि के उद्देश्य से यह योजना सहकारिता विभाग

के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस योजना में लाभार्थियों द्वारा 250 Low input technology Birds के क्षमता वाले फार्म स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना के अर्न्तगत अभी तक 13 जिलों में 5000 कुक्कुट पालकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

- **उत्तराखण्ड चारा नीतिः**-राज्य में मौसमी चारे की कमी को दूर करने और राज्य के पशुपालकों को चारे की उपलब्धता में वृद्धि के लक्ष्य से उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड चारा नीति को मंजूरी दी है। जिससे अगले 05 वर्षों में लगभग 13.174 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त चारा उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान में अन्य गतिविधियों के साथ पशुपालकों को उन्नत मौसमी चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध करायें जा रहे है तथा सूखे चारे (भूसे) पर अनुदान दिया जा रहा है। अब तक लगभग 695 कुन्तल जई, 272 कुन्तल बरसीम,196 कुन्तल मक्का, 66 कुन्तल चरी तथा 25 कुन्तल लोबिया बीज का वितरण किया जा चुका है।
- **मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजनाः** गाय, भैंस, खच्चर, बकरी, भेड़, सूकर और कुक्कुट पालन को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालकों को स्वरोजगार के रूप में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है।पशुपालन से संबंधित स्वरोजगार योजनाओं के बैंक ऋण के ब्याज की धनराशि का 90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना अन्तर्गत 500 गाय यूनिट, 500 भैंस यूनिट, 750 खच्चर यूनिट, 1500 भेड़/बकरी यूनिट, 200 सूकर यूनिट व 750 कुक्कुट फार्मों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष 256 गाय यूनिट, 302 भैंस यूनिट, 154 खच्चर यूनिट, 394 भेड़/बकरी यूनिट, 4 सूकर यूनिट व 64 कुक्कुट फार्मों की स्थापना की जा चुकी है।

विरासत का संरक्षण

- शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्षपर्यन्त, पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया है। इससे वर्ष भर पहाड़ों में पर्यटन, परिवहन और व्यापार के विस्तार की सम्भावनाएं बढ़ी हैं।
- सांस्कृतिक-आध्यात्मिक केन्द्रों में सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने तथा हेली सेवाओं से संयोजन करने के गम्भीर प्रयास किये हैं।
- गोविंद घाट से घांघरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह एवं बिडौर छेवीं पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास द्वारा धरोहर संरक्षण को पर्यावरणीय स्थिरता और आधुनिक सुविधाओं के साथ सहज रूप से एकीकृत किये जाने की योजना है।
- शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे मीठा-रीठा साहिब और श्यामलताल जैसे गौरवशाली विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य व धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है।
- संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किये गये हैं। कांवड़ मेले के आयोजन हेतु ₹ 7 करोड़, अर्द्धकुम्भ मेले की प्रारम्भिक तैयारी हेतु पूंजीगत मद में ₹ 10 करोड़, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु लगभग ₹ 2.64 करोड़, विभिन्न मेलों के आयोजन के लिए ₹ 1 करोड़, संग्रहालय भवन निर्माण हेतु ₹ 3 करोड़ तथा महान विभूतियों की मूर्तियों आदि के लिये ₹ 1.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

युवा शक्ति

- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल व देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण कार्य गतिमान है।
- राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गयी है तथा बड़े पैमाने पर आधारभूत अवसंरचना व खेल उपकरणों की व्यवस्था की गई है।
- रोजगार राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभूतपूर्व अभियान गतिमान है। पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही हैं। बड़ी संख्या में नियुक्तियों का कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किया है।
- राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किये जाने हेतु 13 चिन्हित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टैक्नोलॉजी प्रा.लि. के सहयोग से उच्चीकृत प्रशिक्षण हेतु कार्यशालायें स्थापित की जा रही हैं।
- वर्ष 2024-25 में विकसित एकीकृत औद्योगिक संस्थानों में 45 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 3,370 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है एवं लगभग ₹ 571 करोड़ का निवेश हुआ है।
- "युवा शक्ति" हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किये गए हैं:-
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समग्र रूप से प्रतिपूर्ति हेतु लगभग ₹ 178.83 करोड़, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु समग्र रूप से लगभग ₹ 59.41 करोड़, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु ₹ 23 करोड़, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु ₹ 15 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृति हेतु ₹ 15 करोड़, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल)योजना हेतु ₹ 15 करोड़), साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों हेतु लगभग ₹ 26.64 करोड़, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र हेतु ₹ 5.75 करोड़, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद हेतु लगभग ₹ 16.80 करोड़, उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान हेतु ₹ 5.40 करोड़, विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतु ₹ 10. करोड़, विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु लगभग ₹ 2.41 करोड़, राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय हेतु ₹ 2 करोड़, मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृति हेतु ₹ 2 करोड़, एन.डी.ए. तथा आई.एम.ए. में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरस्कार हेतु लगभग ₹ 1.25 करोड़, उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतु लगभग ₹ 7.11 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद में ₹ 45 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹ 18 करोड़, उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु ₹ 10 करोड़, युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतु ₹ 15 करोड़, युवा महोत्सव के आयोजन हेतु ₹ 5 करोड़, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना हेतु ₹ 5 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना हेतु ₹ 2.50 करोड़, रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतु ₹ 20 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु ₹ 60 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु ₹ 10 करोड़ तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु समग्र रूप से लगभग ₹ 21.60 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

कनेक्टिविटी

राज्य में संयोजकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रभावी माध्यम है। इस संदर्भ में राज्य में सड़क व हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

- सुगम्य संयोजकता के लिए राज्य में बड़े स्केल पर कार्य हो रहे हैं। आगामी वर्ष हेतु लोक निर्माण विभाग ने लगभग 220 किमी. सड़कों का नव निर्माण, 1,000 किमी. पुनर्निर्माण, 1,550 किमी. मार्ग नवीनीकरण, 1,200 किमी. पर सड़क सुरक्षा कार्य के साथ-साथ 37 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
- PMGSY-1 एवं 2 के अन्तर्गत अवशेष 17 बसावटों के संयोजन व 116 कार्य (लम्बाई लगभग-173 किमी.) तथा PMGSY - 3 के अन्तर्गत 191 कार्य (लम्बाई लगभग-1,759 किमी.) को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- राज्य सरकार द्वारा संयोजकता के लिए नागरिक उडड्यन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड नागरिक उडड्यन विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हैलीपैड बनाये जाने हेतु सर्वे कराया गया है।
- क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (RCS) के अन्तर्गत 13 हैलीपोर्ट में से 8 हेलीपोर्ट- चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी), गौचर (चमोली), कोटी कॉलोनी (टिहरी गढ़वाल), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), फलसीमा ट्राटिक (अल्मोड़ा), हल्द्वानी (नैनीताल), सहस्त्रधारा (देहरादून) एवं मुन्स्यारी (पिथौरागढ़) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- दिल्ली-पिथौरागढ़, सहस्त्रधारा-गौचर, देहरादून-नैनीसैनी, हल्द्वानी- मुन्स्यारी, हरिद्वार-चम्पावत तथा पिथौरागढ़- अल्मोड़ा के मध्य हवाई सेवायें संचालित हैं तथा देहरादून-नैनीताल, देहरादून-बागेश्वर, एवं देहरादून-मसूरी के मध्य भी हवाई सेवा प्रारम्भ हो चुकी है।
- संयोजकता को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान भी वर्ष 2025-26 में किये गये हैं। पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹ 1,268.70 करोड़, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई हेतु ₹ 1,065.00 करोड़, नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹ 36.88 करोड़ तथा बस अड्डों के निर्माण हेतु समग्र रूप से ₹ 15 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में राजस्व मद में भी सड़क अनुरक्षण आदि के लिए लगभग ₹ 900 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

ऊर्जा

- मदमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना (15 मेगावाट) का कार्य पूर्ण कर सितम्बर 2024 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ढ़करानी विद्युत गृह में एक मशीन का रिंग मेन यूनिट (आर.एम.यू.) कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।
- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि. द्वारा बैटरी इनर्जी स्टोरेज स्कीम (BESS) की तीन परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि. द्वारा राज्य में अत्याधुनिक ओटोमेटेड डिमान्ड रिसपोंस सिस्टम (ए.डी.आर.एस.) की स्थापना की जा रही है जिससे ग्रिड से ओवरड्राल की स्थिति पर नियंत्रण किया जाना सम्भव हो सकेगा।
- पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (पिटकुल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। वाह्य सहायतित छः परियोजनाओं (लगभग ₹ 520.36 करोड़) के निर्माण हेतु अनुबंध किये गए हैं।
- 132 के.वी. बाजपुर-काशीपुर लाइन एवं 132 के.वी. लोहाघाट-पिथौरागढ़ लाइन का कार्य पूर्ण किया गया है।
- 132 के.वी. काशीपुर-बाजपुर लाइन के द्वितीय सर्किट की स्ट्रीगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है।
- 220 के.वी. सब स्टेशन बरम (पिथौरागढ़) को ऊर्जीकृत किया गया है।
- 132 के.वी. सब स्टेशन भूपतवाला (हरिद्वार) पर 40 एम.वी.ए. (MVA) ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गयी है। यह ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार क्षेत्र में ओवर लोडिंग की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- 132 के.वी. सब स्टेशन पर 132 के.वी. को 'बे' (Bay) का निर्माण किया गया है।
- उत्तराखण्ड प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा रहा है। पी.एम. सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन में हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 47 मेगावाट क्षमता के कुल तेरह हजार एक सौ अड़सठ (13,168) रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हल्द्वानी में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, श्री मनोहर लाल जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री किंजरापु राममोहन नायडू जी से शिष्टाचार भेंट करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।

सफल रेस्क्यू अभियान का बना एक मिशाल मिशन सिलक्यारा

F210

SINCE
1975

उत्तराखण्ड में रिकॉर्ड स्तर पर जीडीपी ग्रोथ

उत्तराखण्ड में रिकॉर्ड स्तर पर राज्य की जीडीपी बढ़ी और बेरोजगारी घटी

देश में सर्वोच्च अपना उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज हमारा प्रदेश अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (SDG INDEX) 2023-2024 की रिपोर्ट में उत्तराखण्ड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राज्य सरकार में कैबिनेट के सहयोगियों, शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी बहुत बधाई। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ विकसित उत्तराखण्ड की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए सर्वस्पर्शी एवं सर्वांगीण विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड के नाम, एसडीजी 2023-24 में उत्तराखण्ड देश में प्रथम

नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी

रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने सर्वाधिक अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है।

उत्तराखण्ड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश मे पहला स्थान हासिल किया है।

उत्तराखण्ड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।

रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने सर्वाधिक अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है।

राज्य वृक्ष : बुराँस

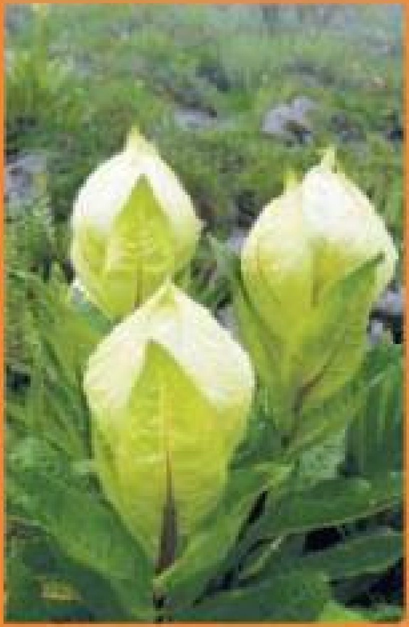
राज्य पुष्प : ब्रह्मकमल

राज्य पशु : कस्तूरी मृग

राज्य पक्षी : मोनाल

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून द्वारा प्रकाशित एवं एलाईड प्रिंटर्स, देहरादून द्वारा मुद्रित।
फोन : 0135-2662971, 2662369 फैक्स : 0135-2662334 ई-मेल: infodirector.uk@gmail.com वेबसाइट: www.uttarainformation.gov.in